स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–19, अंक–3, फाल्गुन 2067, मार्च 2011

विदर्भ विशेषांक

संपादक
विक्रम उपाध्याय

कार्यालय
धर्मक्षेत्रा, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी
दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

अनुक्रम

आवरण कथा
राजकोषीय घाटे में कमी की सच्चाई
– डॉ. अश्विनी महाजन /4

स्वदेशी पत्रिका (विदर्भ विशेषांक)
अतिथि संपादक का मनोगत
– अजय पत्की /6

विश्लेषण
प्रचुर साधन सम्पदा के बावजूद विदर्भ पिछड़ा क्यों?
– डॉ. शरद निंबालकर /7

कार्यवृत्त
विदर्भ प्रांत में स्वदेशी जागरण मंच का कार्य (1991 से 2009 तक) – प्रा. अविनाश साकले /10

विदर्भ प्रदेश – वार्षिक कार्यवृत्त : 2010–11
– प्रा. अजय पत्की /12

नागपुर – कार्यवृत्त – आशुतोष पाठक /12

मानव सेवा : सेवाग्राम से शोधग्राम तक एक यात्रा
– पराग/अरुंधती पांढरीपांडे/23

समीक्षा : विदर्भ के औद्योगिक विकास की समीक्षा
– किशोर काले /24

दृष्टिकोण : प्रस्तावित ताप विद्युत केंद्रों से विदर्भ का विकास होगा या विनाश? – धनंजय भिड़े /26

इतिहास : प्राचीन विदर्भ
– श्रीपाद केशव वितले /27

लेख : दीनदयाल किसान विकास प्रकल्प
– प्रदीप वडनेरकर /28

पर्यावरण : प्रदूषित होती जीवनदायिनी
– अमोल पुसदकर /30

प्रतिक्रिया : बजट 2011–12 में आम आदमी गायब
– डॉ. सूर्यप्रकाश अग्रवाल /32

ढीला बजट – लेकिन सही दिशा में
– डॉ.भरत झुनझुनवाला /34

पाठकनामा/2, आंदोलन/35

पाठकनामा

हर बार की तरह आम व्यक्ति पर मार

प्रणव मुखर्जी ने इस बार जन अपेक्षा के उलट अपना बजट पेश किया। बजट भी ऐसा जिसमें टीवी, कम्प्यूटर, कारें और इलैक्ट्रॉनिक्स माल सस्ता, बाकी सब महंगा। यह बजट भी अमीरों के हितों के लिए बनाया गया है, जिसमें आम व्यक्ति को कहीं भी जगह नहीं दी गई है। इस बजट से मामूली आयकर छूट के अलावा आम आदमी को मिला ही क्या। व्यापारी वर्ग को भी निराशा मिली है। वह करों में छूट चाहता था, लेकिन वित्त मंत्री ने अलग अलग तरीकों से कई और कर लाद ही दिया है। जनता को बजट या अन्य करों से कोई लेना देना नहीं। उसकी चिंता महंगाई को लेकर है। इस बजट से महंगाई कम होने के बजाय और बढ़ जाएगी। खुद वित्त मंत्री यह मान चुके हैं। बेरोजगार नवयुवक और गरीबों को क्या मिलने वाला है? उसको तो दर–दर की ठोकरें खानी ही है।

वित्त मंत्री चाहते तो अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाते जैसे पहली कार पर सामान्य टैक्स, दूसरी कार लेने पर ज्यादा टैक्स लगाते, इसी तरह पहले मकान पर कम टैक्स, दूसरा मकान खरीदने पर ज्यादा कर। इसी तरह विलासिता सामानों पर कर अधिक करना चाहिए। परंतु वित्तमंत्री तो अमीरों के हितैषी है उन्हें गरीबों से क्या लेना–देना। खैर वक्त आ गया है कि आज भारतीय जनता सोचें कि वित्तमंत्री के भरोसे न रहकर प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर के लोगों में आपसी सहमति बनें कि कैसे इस महंगाई से पीछा छुड़ाया जाए। तभी भारत की गरीब जनता का भला होगा अन्यथा इसी तरह बजट हर साल आता रहेगा और गरीब व्यक्ति और गरीब होता चला जाएगा।

कहने को वित्त मंत्री ने किसानों को खुश करने वाला बजट पेश किया है। पर किसानों को सीधे सब्सिडी देने के एक मात्र फैसले के अलावा और क्या खास है। किसानों को निरंतर समस्यांओं का सामना कर पड़ रहा है। वे कभी खाद के लिए परेशान होते हैं तो कभी बीज के लिए। कभी उनकी फसल मारी जाती है तो कभी साहूकारों से उनका शोषण होता है। आखिर वह दिन कब आएगा जब किसानों को नियमीत आय होगी और वे किसानी को अपना रोजगार भी बना सकेंगे। सोनिया गांधी की इच्छा के अनुरूप इस बार खाद्य सुरक्षा विधेयक आने की चर्चा है, यदि यह होता है तो ही लगेगा कि सरकार गरीबों और किसानों के हित में सोंचती है।

– राकेश कुमार दास, मीडिया अपार्टमेंट, अभय खण्ड, गाजियाबाद

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

"धर्मक्षेत्र" शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com
अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 100 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्क: 1,000 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

(ध्यानार्थ : कृपया अपना नाम व पता साफ अक्षरों में लिखें)

उन्होंने कहा

सीवीसी की नियुक्ति के लिए मैं पूरी तरह जिम्मेदार हूँ। इस मामले में गठबंधन की कोई मजबूरी नहीं थी। मैं थॉमस की नियुक्ति को गैरकानूनी करार देने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूँ।

– प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह

बेरोजगारी तो वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की आंखों से ओझल ही हो गई। युवाओं को भी बजट से निराशा हुई है। वहीं, रसोई की मार झेल रही महिलाओं पर भी ध्यान नहीं दिया गया है।

– सुषमा स्वराज

मैं भारतीय सिनेमा में किसी भी तरह के बदलाव का विरोधी हूँ। पश्चिमी सिनेमा भले ही बालीवुड की आलोचना करे, लेकिन भारतीय सिनेमा देश को एक सूत्र में पिरोए रखने का एक सशक्त माध्यम है।

– अमिताभ बच्चन

संपादकीय

न्यायालय का हंटर, दौड़ती सरकार

आम आदमी को बजट के बड़े–बड़े आंकडे समझ में नहीं आते। उसके लिये बजट उसकी आमदनी और खर्च के बीच के अन्तर का हिसाब–किताब है। बजट से पहले आम आदमी एक ऐसी सूची बनाता है जो उसकी परेशानी के कारक होते हैं और यह सोचता है कि इस सूची के अनुसार यदि वित्त मंत्री कोई प्रावधान करते हैं तो उसका जीवन थोड़ा सरल हो सकता है। नये वित्त वर्ष के लिये घोषित बजट में वह आम आदमी सूची लिये खड़े यह सोचता रहा कि आखिर उसके लिये इसमें है क्या? जो नौकरीशुदा लोग हैं उनको वित्त मंत्री ने यह बताया कि अब आयकर की सीमा 1,80,000/–रूपये कर दी गयी है। यानि लगभग 15,000 रूपया महीना कमाने वाले लोगों को कोई कर नहीं देना होगा। यही नौकरीपेशा आदमी यह सोचता रहा कि उसके लिये इसका क्या मतलब? कुल मिलाकर 2 हजार रूपये की सालाना कर छूट मिली उसके बदले सरकार उससे लेगी क्या, यह भी सवाल उसके मन में आया। बजट पर जब थोड़ा गंभीर विश्लेषण हुआ तब उस आम आदमी को यह पता चला कि वित्त मंत्री ने सांस लेने पर कर लगाने को छोड़कर कहीं कोई ऐसा क्षेत्र छोड़ा ही नहीं जहां वह बच सके। इस बार जिन सेवाओं पर कर लगाया गया है। वह सीधे आम आदमी पर भार बढ़ायेगा। कपड़े खरीदेगा तो उसे अतिरिक्त कर देना होगा, होटल में खाना खाने जायेगा तो उसे अतिरिक्त कर देना होगा और तो और अब उसका बीमार होना भी उसके लिये ज्यादा मंहगा पड़ेगा। भविष्य के लिये कुछ जमा करने की उसकी आदत पर भी सरकार की मार पड़ी अब बीना योजनाओं पर भी सेवाकर लाद दिया गया है। पहले से ही महंगाई का दंश झेल रहा आम आदमी यह सोचता रह गया कि आखिर सरकार से कोई राहत उसे मिलेगी या नहीं। जब कुछ आर्थिक विश्लेषकों ने वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी से यह सवाल पूछा कि आपका यह बजट क्या महंगाई को और नहीं बढ़ायेगा तो उन्होंने झेंपते हुए कहा कि ज्यादा नहीं थोड़ी महंगाई बढेगी। इस थोड़ी की परिभाषा सरकार देना नहीं चाहती, हां मंहगाई बढ़ाने की अपनी हवस को वित्त मंत्री ने विकास के मुद्दे से जोड़ दिया और उन्होंने लोगों को समझाया कि 8 फीसदी विकास दर को बनाये रखने के लिये आम आदमी को थोड़ा और मरना चाहिए, उन्होंने कहा कि मंहगाई की सूचक मुद्रास्फीति की दर कम तो की जा सकती है लेकिन इससे विकास पर असर पड़ेगा। कोई इनसे पूछे कि देश में विकास सिर्फ बड़े लोगों के लिये है, केवल कंपनियों को या औद्योगिक घरानों को ही जीने का अधिकार है। आम आदमी इस विकास में कहीं मायने रखता है या नहीं।

अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बेचारगी के शिकार हैं। लगातार उन पर हमले हो रहे हैं, कभी घोटाले को लेकर तो कभी अनैतिकता को लेकर। सर्वोच्च न्यायालय में सरकार पर ऐसी–ऐसी टिप्पणियां की हैं जिन्हें किसी भी प्रधानमंत्री के लिये एक शर्मनाक स्थिति कही जा सकती है। बोफोर्स, काले धन, सीवीसी की नियुक्ति और टूजी स्पैक्ट्रम घोटाला जैसे मामलों में सरकार की एक बार नहीं कई बार छीछालेदार हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने तो यहां तक कहा कि "What the hell is going on" इसका हिन्दी में आशय है कि सरकार ने क्या नर्क मचा रखा है। यह टिप्पणी काले धन के मामले में आरोपी हसन अली खां के प्रति सरकार के नरम रवैये पर की गयी थी। अब सर्वोच्च न्यायालय प्रधानमंत्री को यह बताने पर विवश हो गया है कि देशद्रोहियों के खिलाफ सरकार क्या करेगी। यह किसी भी सरकार के लिये शुभ लक्षण नहीं हैं। पर प्रधानमंत्री पर इसका असर नहीं है। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने उनके दामन पर एक और दाग जड़ दिया है। नैतिकता का तकाज़ा यह था कि सरकार पूरी जिम्मेदारी लेते हुए इस मसले पर देश से माफी मांगती, पर प्रधानमंत्री यहां भी अपनी बेचारगी दर्शा गये। उनका यह कहना कि कार्मिक विभाग के राज्यमंत्री ने मुख्य सतर्कता आयुक्त के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी उन्हें नहीं दी थी, यह दर्शाता है कि सरकार में ही प्रधानमंत्री की स्थिति कितनी कमजोर है। उनके अधीन काम करने वाला एक नेता ऐसी सूचनायें दबाकर रख सकता है जो बाद में सरकार और संविधान के माथे पर कलंक साबित हो सकती है और उस नेता को कांग्रेस नेतृत्व इनाम देकर महाराष्ट्र जैसे बड़े राष्ट्र का मुख्यमंत्री पद भेंट कर सकता है।

हसन अली गिरफ्तार हो गया। उसकी तमाम गैर कानूनी एवं देश विरोधी गतिविधियों की अब जांच शुरू हो गयी है। प्रवर्तन निदेशालय के पास अब उसके खिलाफ दस्तावेज़ भी मिल गये हैं। पर देश को यह समझ में नहीं आ रहा कि यह सरकार किन कारणों से हसन अली के प्रति अब तक नरम बनी रही। अगर सर्वोच्च न्यायालय दखल नहीं देता तो सरकार को उसकी गिरफ्तारी के लिये नहीं झकझोरता, तो अब तक हसन अली देश की व्यवस्था को मुंह चिड़ाता रहता। सरकार के पास 2008 में ही इस बात की ठोस सूचना आ गयी थी कि इस व्यक्ति ने हथियारों की तस्करी, नशीली दवाओं के व्यापार और आतंकवादियों को सहायता देकर 35 हजार करोड़ रूपये से भी अधिक का काला धन इकट्ठा कर रखा है। उसने यह रूपये रिवस बैंक के एक खाते में जमा कर रखा है, इसकी खबर भी सरकारी विभागों के पास थी लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ उसके गहरे संबंधों के कारण सरकारी विभाग आंखें बंद किये रहे। अब जब सर्वोच्च न्यायालय ने हसन अली के खिलाफ देशद्रोह और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के मामलों में चलाने की सलाह दी है, तब जाकर इन विभागों में हरकत शुरू हुई है। अब देखना यह है कि देश का पैसा हसन अली जैसे शातिर अपराधियों की तिजोरी से बाहर आता है या नहीं।

आवरण कथा

राजकोषीय घाटे में कमी की सच्चाई

आवश्यकता इस बात की है कि सरकार अपने गैर जरूरी खर्चों पर लगाम लगाए, कारपोरेट क्षेत्र को दी जाने वाली अनावश्क छूटों को समाप्त किया जाए और इस प्रकार से राजस्व में होने वाले घाटे को दूर किया जाए। ऐसा होने पर ही देश मंहगाई डायन से बचकर विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ पायेगा।

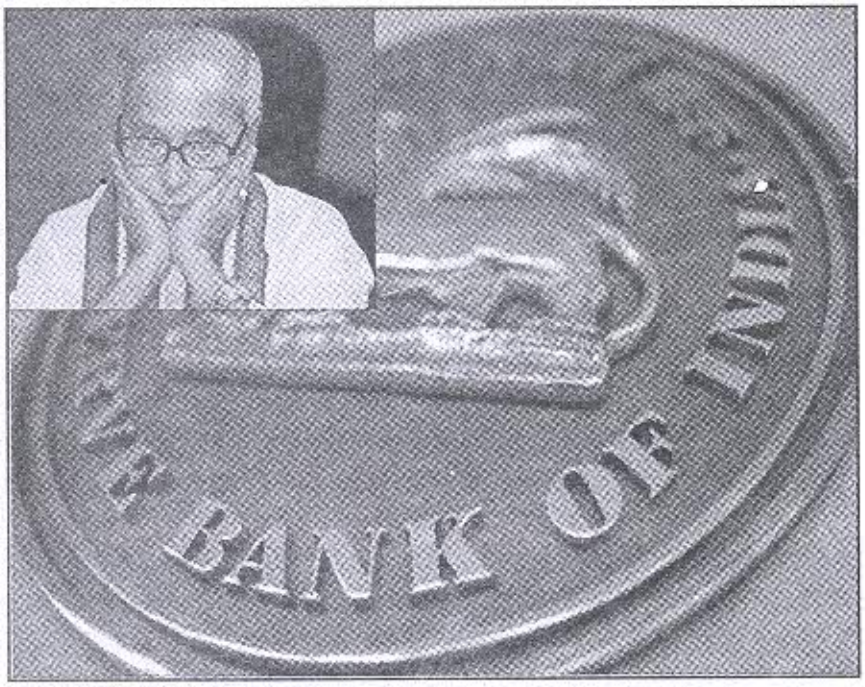

अधिक कर्ज उठाने से भविष्य के लिए सरकार की देनदारियां बढ़ जाती है और उसे बढ़े हुए कर्ज पर ब्याज देना पड़ता है। पिछले कुछ समय से सरकार के कुल बजट का 20 प्रतिशत से भी अधिक ब्याज की अदायगी में ही चुक जाता है, जिसके कारण सरकार सामाजिक सेवाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और विकास के लिए अन्य जरूरी मदों पर खर्च नहीं बढ़ा पाती।

■ डॉ. अश्विनी महाजन

वित्त मंत्री जब आगामी वर्ष 2011–12 का बजट संसद में पेश कर रहे थे, तो जो यह समाचार फ्लैश हुआ कि वर्ष 2010–11 के लिए बजट में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.5 प्रतिशत रखा गया था, वह संशोधित अनुमानों के अनुसार घट कर 5.1 प्रतिशत ही रह गया है। यह देश के लिए एक सुखद् समाचार था। यह हम सब जानते है कि जब सरकार अपनी आमदनी से अधिक खर्च करती है तो उससे राजकोषीय घाटा उत्पन्न होता है। इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार या तो बाजार से कर्ज उठाती है या भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज के माध्यम से देश में अतिरिक्त कैरेंसी छापी जाती है। अधिक कर्ज उठाने से भविष्य के लिए सरकार की देनदारियां बढ़ जाती है और उसे बढ़े हुए कर्ज पर ब्याज देना पड़ता है। पिछले कुछ समय से सरकार के कुल बजट का 20 प्रतिशत से भी अधिक ब्याज की अदायगी में ही चुक जाता है, जिसके कारण सरकार सामाजिक सेवाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और विकास के लिए अन्य जरूरी मदों पर खर्च नहीं बढ़ा पाती। यदि सरकार इस राजकोषीय घाटे की भरपाई अधिक नोट छापकर करती है, तो उससे मुद्रा स्फीति बढ़ती है। दोनों ही प्रकार से राजकोषीय घाटा बढ़ने पर देश का विकास तो बाधित तो होता ही है, आम जन के लिए कठिनाईयां बढ़ जाती है। ऐसे में जब यह समाचार आया कि राजकोषीय घाटा सिमट कर 5.1 प्रतिशत ही रह गया है, तो शेयर बाजारों ने इसका जोशो–खरोश के साथ स्वागत किया और मुम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 600 अंक बढ़ गया, लेकिन जब बजट आंकड़े आने पर सच्चाई सामने आ गयी और उसी दिन बाजार के बंद होने तक वह संवेदी सूचकांक 480 अंक नीचे आ गया।

एफ.आर.बी.एम एक्ट और राजकोषीय घाटा

कुछ वर्ष पूर्व सरकार ने एफ.आर.बी.एम. कानून पास करते हुए स्वयं पर यह अंकुश लगाया था कि राजकोषीय घाटे को कम करते हुए उसे तीन वर्षों में 2.5 प्रतिशत तक लाया जाएगा, लेकिन सरकार अपने इस संकल्प पर अडिग न रह सकी और अपने ही संकल्प की धज्जियां उड़ाते हुए वर्ष 2008–09 में राजकोषीय घाटे को लगभग 7 प्रतिशत तक पहुंचा दिया गया। सरकार ने इसके लिए यह तर्क

दिया कि वैश्विक मंदी से उबरने के लिए सरकार को एक ओर करों में छूट देनी पड़ी और दूसरी ओर सरकारी व्यय बढ़ाना पड़ा। वित्त मंत्री का कहना है कि अब बदली हुई परिस्थितियों में सरकार एफ. आर.बी.एम. एक्ट के अनुरूप अपने राजकोषीय घाटे को कम करके उसे 2.5 प्रतिशत पर लाने के लिए संकल्पित है। इसके लिए वित्त मंत्री ने यह कहा कि वर्ष 2010–11 में संशोधित अनुमानों के अनुसार यह घाटा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 5.1 प्रतिशत ही रहेगा। लेकिन विशेषज्ञों का एक बहुत बड़ा वर्ग सरकार के इस दावे से सहमत नहीं है।

राजकोषीय घाटे में कमी की सच्चाई

हालांकि सरकार यह दावा कर रही है कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में यह बजट अनुमानों में 5.5 प्रतिशत से घटकर 5.1 प्रतिशत लाया गया है, लेकिन यदि हम बजट आंकड़ों पर नजर डाले तो पता चलता है कि वर्ष 2010–11 के लिए बजट अनुमानों के अनुसार राजकोषीय घाटा 3,81,408 करोड़ रूपये रखा गया था, संशोधित अनुमानों के अनुसार यह घाटा 4,00,998 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है, यानि लगभग 20 हजार करोड़ रूपये अधिक। ऐसे में राजकोषीय घाटा कम कैसे हुआ यह समझ से परे है। आंकड़ों की कारीगरी के माध्यम से ही इस बढ़े हुए राजकोषीय घाटे को कम दिखलाया जा सकता है।

सरकारी हलकों में यह बात कही जा रही है कि राजकोषीय घाटे को कम दिखाने में मुद्रा स्फीति (महंगाई) ने सरकार को मदद की है। इस बात को समझने के लिए हम आंकड़ों का ही उपयोग करते हैं। सीएसओ के 2010–11 के जीडीपी के अनुमानों के अनुसार चालू कीमतों पर वर्ष 2010–11 में जीडीपी की संवृद्धि दर 19 प्रतिशत रहने का अनुमान है। स्थिर कीमतों पर जीडीपी की संवृद्धि दर मात्र 9 प्रतिशत ही है। विडंबना यह है कि राजकोषीय घाटे को चालू कीमतों पर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में ही आंका जाता है। ऐसे में चालू कीमतों पर 19 प्रतिशत बढ़ी हुई जीडीपी के कारण राजकोषीय घाटा 5.1 प्रतिशत ही दिखाई देता है। हम कल्पना करें कि महंगाई यदि 10 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत होती तो राजकोषीय घाटा मात्र 4.2 प्रतिशत ही दिखाई देता। इसका मतलब यह नहीं है कि राजकोषीय घाटा कम हुआ है। इसका मतलब यह है कि मंहगाई के कारण राजकोषीय घाटा कम दिखाई दे रहा है।

वर्ष 2011–12 के बजट अनुमानों के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.6 प्रतिशत ही रहेगा। यदि हम इसे नजदीक से देखें तो पता चलता है कि वर्ष 2010–11 के बजट अनुमानों के तुलना में वर्ष 2011–12 का राजकोषीय घाटा लगभग 31,000 हजार करोड़ रूपये अधिक है। चाहे जीडीपी के प्रतिशत के रूप में इसके 5.5 प्रतिशत से घटकर 4.6 प्रतिशत तक घटने का दावा किया जा रहा है। लेकिन यदि इस वर्ष के बजट घाटे और सरकारी दावों का निकटता से अध्ययन किया जाए तो निम्नलिखित बातों पर गौर करना जरूरी होगा –

पिछले लगभग एक वर्ष से खाद्य सुरक्षा कानून बनाने और उसे लागू करने की कवायद चल रही है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने पुनः इस बात को दोहराया कि सरकार खाद्य सुरक्षा बिल संसद में पेश करेगी। हालांकि सरकार स्वयं भी खाद्य सुरक्षा कानुन के बारे में अधिक उत्साह नहीं दिखा रही, फिर भी यदि इस कानून को लागू किया जाता है तो लगभग 30 से 40 हजार करोड़ रूपये हर वर्ष इस पर खर्च होगें। लेकिन विडंबना यह है कि बजट में इस मद के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यदि यह कानुन बनता है तो राजकोषीय घाटे में और वृद्धि संभव है।

हर वर्ष रोजगार गारंटी कार्यक्रम के विस्तार हेतु पहले से अधिक धन आवंटित किया जाता रहा है। इस वर्ष हालांकि मजदूरी दर में वृद्धि करने की बात की गई है, लेकिन इस हेतु बजट में प्रावधान दिखाई नहीं देते हैं।

इस वर्ष सब्सिडी बिल में 20,000 करोड़ रूपये की भारी कटौती भी की गई है। संभव है कि परिस्थितियों के अनुरूप इस कटौती को अंजाम देना संभव न हो। ऐसे में राजकोषीय घाटा और भी बढ़ सकता है।

इन सब कारणों से सरकार के वे समस्त दावे कि राजकोषीय घाटा कम होने से महंगाई पर लगाम कसी जा सकेगी, निजी निवेष को बढ़ावा मिलेगा और देश सरपट विकास के रास्ते पर आगे बढ़ पायेगा, तर्कहीन जान पड़ते है। ध्यातव्य है कि कारपोरेट क्षेत्र को दी जाने वाली छूटों के कारण हर वर्ष बजट में राजकोष का नुकसान बढ़ता ही चला जाता है। वर्ष 2010–11 में यह नुकसान 511630 करोड़ रूपये रहेगा जबकि वर्ष 2009–10 में यह 482432 करोड़ रूपये था। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार अपने गैर जरूरी खर्चों पर लगाम लगाए, कारपोरेट क्षेत्र को दी जाने वाली अनावश्क छूटों को समाप्त किया जाए और इस प्रकार से राजस्व में होने वाले घाटे को दूर किया जाए। ऐसा होने पर ही देश महंगाई डायन से बचकर विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ पायेगा। ❑

:: अतिथि संपादक का मनोगत ::

प्रतिमाह प्रकाशित होने वाली स्वदेशी पत्रिका पाठकों को वौद्धिक सामग्री प्रदान करने वाला प्रभावी उपकरण है। देश के ख्यातनाम चिंतक, लेखक, अर्थशास्त्री पत्रिका में लिखते हैं। इसका उपयोग सभी कार्यकर्ताओं को अपनी प्रेरणा बनाएं रखने के लिए तथा कार्यप्रवण रहने के लिए होता रहता है। साथ ही देश की गतिविधियों के बारे में प्रत्यक्ष कार्यरत व्यक्तियों के माध्यम से जानकारी मिलती रहती है।

गत कई वर्षों से पत्रिका का शुल्क भरना तथा आए हुए लेखों को पढ़ना यह क्रम जारी रहा। दो वर्ष पूर्व स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठक मा. श्री कश्मीरीलालजी ने प्रांत संयोजकों की बैठक में एक विषय रखा। प्रत्येक प्रांत का, स्वदेशी पत्रिका के विकास में योगदान होना चाहिए। इस विकास के कई आयाम हो सकते है। श्री कश्मीरीलालजी ने अपनी विशिष्ट शैली में कार्यकर्ताओं से ऐसे आयामों की चर्चा की। प्रस्तुति का स्वरूप, विज्ञापन, आर्थिक पक्ष, संपादन, समाज के समविचारी तथा आर्थिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में स्वदेशी पत्रिका का प्रसार आदि तथा अन्य पक्ष भी चर्चा में सम्मिलित रहे। श्री कश्मीरीलालजी की चर्चा ने सभी प्रांत संयोजकों को उनके अपने प्रांत का पत्रिका संचालन में नगण्य योगदान है इसका अहसास कराया। सभी ने स्वयं होकर स्वीकार किया कि अपने–अपने प्रांत की विशेषताओं को उजागर करनेवाला तथा प्रांत का सर्वस्पर्शी परिचय कराने वाला विशेषांक निकाला जाए। विदर्भ विशेषांक भी इसकी एक कड़ी है। स्वदेशी जागरण मंच ने जून 2010 में रायपूर में आयोजित राष्ट्रीय परिषद् में राजकीय दृष्टि से संचालित संपूर्ण महाराष्ट्र को एक प्रांत करने की घोषणा की। इसके पूर्व स्वदेशी जागरण मंच की व्यवस्था से महाराष्ट्र में विदर्भ, देवगिरी, कोंकण तथा पश्चिम महाराष्ट्र ऐसे कुल 4 प्रांत थे। अब इन चारों को मिला दिया गया हैं किंतु विदर्भ विशेषांक की घोषणा इस सम्मिलीकरण के पूर्व ही हुई थी, इसलिए यह अंक भले ही विलंब से किंतु पूर्व निर्धारण निर्णय के अनुसार अपने समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रांत के सभी कार्यकर्ताओं के लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है क्योंकि यह अपने आपमें एक अनूठा एवं इस प्रकार का पहला ही प्रयास है।

इस अंक में विदर्भ के महापुरुषों की जानकारी, विदर्भ की ताकत एवं कमजोरियां, जंगल, पर्यावरण, नदियां, प्रचुर खनिज उपज आदि के बारे में तथा प्रांत का स्वदेशी संबंधित गत कुछ महिनों का कार्यवृत्त तथा छायाचित्र इनकी प्रस्तुति की गई है। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय समृद्धि के पश्चात् विदर्भ पिछड़ा क्यों रहा है यह सभी का सदा से ही चिंता एवं चर्चा का विषय रहा है। विदर्भ के यवतमाल, वर्धा जिले केवल देश में ही नहीं अपितु संसार में किसानों की आत्महत्याओं के लिए चर्चित है। सामाजिक संस्थाओं की ओर से इस जटिल समस्या के निदान में कुछ कार्य किया गया है, उसे भी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

विशेषांक प्रकाशित करने के लिए आवश्यक अनुभव, साधन, लेखन कार्य में अरुचि जैसे अभाव बड़ी मात्रा में ध्यान में आए हैं। विशेषांक के इस उपक्रम के कारण स्वदेशी जागरण कार्य के लिए समाज में कार्यरत सभी प्रकार के लोगों से संबंध प्रस्थापित करना कितना आवश्यक है इसका भी अनुभव हुआ है। इन सभी अभावों के होते हुए भी जिन लेखकों व विज्ञापनदाताओं ने इस कार्य को संपन्न करने में अपना सहयोग दिया है उनका हृदय से आभार।

अजय पत्की
संयोजक, महाराष्ट्र प्रांत

प्रचुर साधन सम्पदा के बावजूद
विदर्भ पिछड़ा क्यों?

विदर्भ में औसतन प्रति व्यक्ति 5 एकड़ भूमि धारक है। कुल 23 लाख कास्तकार है। 37 लाख मजदूर है। 1 करोड़ 40 लाख ग्रामीण जनसंख्या है। नागरी जनसंख्या 66 लाख है। सूखी खेती में एक परिवार का गुजारा नहीं हो सकता। एक बैल जोड़ी के लिए 15–20 एकड़ भूमि अगर है तो ही फायदेमन्द है। छोटे किसान को बैल जोड़ी रखना संभव नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी बंटवारे से भूमि ओर कम हो जाती है।

■ डॉ. शरद निंबालकर

भारत के विकास में विदर्भ का योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक रहा है। वर्तमान में शासकीय महाराष्ट्र प्रदेश का यह एक विभाग है। प्राचीन काल में देखें। प्रभु रामचन्द्रजी की दादी विदर्भ से थी। देवकी की माता भी यही की थी। ऋषि अगस्त्य और उनकी पत्नि लोपामुद्रा, राजा नल की पत्नि दमयंती, महाकवि कालिदास, मुकुंदराज तथा भगवान श्रीकृष्ण की पटरानी रूक्मिणी, माता जीजाबाई– ये सब विदर्भ से ही थे। ये सारे तथ्य दर्शाते हैं कि विदर्भ प्रदेश सांस्कृतिक, साहित्यिक दृष्टि से कितना वैभवसंपन्न था।

विदर्भ यानि विशेष प्रकार का दर्भ (तृण) उपजाने वाली भूमि, ऐसा भी एक अर्थ है। प्राचीन काल से भारत में मालवा, गुजरात, दख्खन का कुछ हिस्सा आदि जो समृद्ध भू–भाग रहे हैं, उनमें विदर्भ अग्रणी रहा है। यहां की जमीन बड़ी उपजाऊ है। भौगोलिक दृष्टि से नैऋत्य–ईशान्य तथा पूर्व–पश्चिम दोनों तरफ की वायु का लाभ मिलने से सात सौ – आठ सौ मिलिमीटर का अच्छा पर्जन्यमान है। कपास, ज्वर, धान की भूमि मानी जाती है। कपास उपजाने वाली भूमि 13 लाख हेक्टर, दालों की 13 लाख हेक्टर, तृणाधान्य की 13 लाख हेक्टर और इसके साथ ही धान की भूमि 7.5 लाख हेक्टर है (जबकि धान का प्रदेश कोंकण माना जाता है जिसमें यह केवल 4.5 लाख हेक्टर है) इस तरह विदर्भ में 50 लाख हेक्टर की उर्वरा भूमि है। वर्धा, वैनगंगा जैसी बारहों मास बहने वाली बड़ी–बड़ी नदियां है। 27 लाख हैक्टर का वन क्षेत्र, प्रचुर खनिज संपदा, साल में नौ से दस माह सूर्यप्रकाश– ये सारी संपत्ति और ऊर्जा के बड़े स्त्रोत है।

वर्षा का जल प्रचुर मात्रा में होते हुए भी सिंचाई का प्रबंध योग्य प्रकार का नहीं है। यही बड़ी समस्या है। स्वतंत्रता के बाद से भूस्तरीय जल तथा भूजल की और पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। इसका अगर शीघ्र उपाय हो तो फिर से विदर्भ की भूमि सुजलाम्, सुफलाम् बन सकती है। शासन तथा जनसहभागिता से प्रयास किए जाए तो फलस्वरूप जल की समस्या हल हो सकती है। इस से उद्योगों का भी विकास हो सकता है। गोसी खुर्द, वर्धा जैसी बड़ी बान्ध परियोजनाएं कब से अधूरी पड़ी है। मूलभूत सुविधाओं के विकास के बिना समृद्धि कैसे संभव है? पानी की कमी से तापमान बढ़ रहा है, जीव जन्तु समाप्त हो रहे हैं। जैव–विविधता (Bio Diversity) खतरे में पड़ गयी है।

ऊपर का (वर्ष का) पानी तो बहुत है। विदर्भ के लगभग 15,150 गांवों तक पानी पहुंचने के लिए Integrated Water Shed का विचार होना चाहिए। पांच–पांच, दस–दस गांवों के क्लस्टर्स बनाए जाए। इसी से 70 प्रतिशत पानी भूमि के अन्दर संग्रहित होगा, बचा 30 प्रतिशत नदियों में बह जायेगा। इसके फलस्वरूप कृषि उद्योग, कृषि उपज में बढ़ोतरी होगी। 'हमारा बीज' योजना, पोल्ट्री, कृषि उत्पाद प्रक्रिया उद्योग आदि को प्रोत्साहित किया जाए। पानी का इतना महत्व है कि नदियों को जीवनरेखा माना जाता है। चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र, पानी के बिना विकास की कल्पना संभव नहीं है। उचित जलप्रबंधन न होने से शुष्क खेती की सारी समस्याएं खड़ी हुई है। बान्ध बनाया तो जाता है खेती के लिए, परन्तु उसका उपयोग पेयजल और उद्योगों के लिए होता है। कृषि उपेक्षित रह जाती है। यही पानी फिर सबकी आंखों में पानी लाता है।

इस समस्या का उपाय अगर होता है तो फसलों में बदलाव, जैविक कृषि कम लागत की शाश्वत खेती आदि सफलतापूर्वक किए जा सकते है। तभी गांधीजी और राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की स्वयंपूर्ण ग्राम (Self Sustained Village) की कल्पना साकार हो सकती है। गांवों में रोजगार उपलब्ध हो सकते हैं।

पानी की मुख्य समस्या सुलझने के पश्चात कृषि उत्पाद प्रक्रिया उद्योगों को

सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाए। कार्पोरेट क्षेत्र धन इसमें निवेश करें। कृषकों के और जनसहभागिता से विस्तृत संरचना (Network) आवश्यक है। उत्पादन और विपणन में सरकार द्वारा सहायता मिलें। इस से LPG (लिबरलाईजेशन, प्रायवेटाइजेशन, ग्लोबलाईजेशन) के आक्रमण के दौर में ग्रामीण उद्योगों को सहारा मिलेगा। सरकार ऐसी नीति बनाएं, तभी कृषक आश्वस्त होंगे। अन्यथा आत्म हत्याएं होती रहेंगी। कच्चे माल से पक्का माल बनने तक जो अत्याधिक मूल्यवृद्धि होती है, उसमें बेचारे किसान को कुछ लाभ नहीं मिलता, मलाई अन्य लोग खा जाते है। केवल कुछ कृषि उत्पाद के मूल्य बांध दिये गये हैं और अन्य वस्तुओं की दरों पर कोई नियंत्रण नही है तब घाटा किसान का ही होगा। दो–तीन रूपये किलो अनाज की योजना गलत है। सस्ती लोकप्रियता पाने की जुगत में घाटा किसान को ही उठाना पड़ता है।

ऐसी स्थिति सुधारने हेतु कुछ संकल्प करने होंगे। कास्तकारों की सुरक्षा, सबलीकरण हेतु कदम उठाने होंगे। कृषि उत्पाद प्रक्रिया (मूल्यवर्धन) में किसान को उचित भागीदारी देनी होगी। 'फ्रॉम प्लॅन्ट टू प्लेट (फिनिश्ड प्रॉडक्ट)' अर्थात् धान्य से धन बनाने की व्यावसायिक खेती फायदेमन्द हो सकती है। कपास से कपड़ा, आलू से आलू चिप्स और अन्य उदाहरण ऐसे है जिसमें हजार गुना मूल्यवर्धन होता है, परंतु किसान लाभ से वंचित है। अन्त में फिर ग्राहक भी वही है, जिसे इतनी महंगी वस्तु खरीदनी पड़ती है। कृषि उत्पाद से धन तो निर्मित हो रहा है, परंतु किसान वंचित है, बदहाल है। शुष्क खेती वाले पर इसका आघात अधिक होता है। उसे 3 क्विंटल अनाज मिलता है, तो सिंचाईवाले किसान को उतनी ही भूमि पर 20 क्विंटल मिल जाता है। प्रतिरोधक शक्ति (Sustaining Power) में इतना अन्तर है, तो शुष्क खेतीवाला तो कभी न कभी टूटेगा ही।

71 हजार करोड़ का जो पैकेज मिला है, उसका लाभ पांच एकड़ वाले सिंचन सुविधावालों को ही मिला है। विदर्भ में सूखी खेती करने वाले 85 प्रतिशत है/अच्छी तरह (Effective) सिंचित भूमि केवल 4 से 5 प्रतिशत ही है (न कि 12 प्रतिशत) जिनको पैकेज का लाभ मिला है। अतः समस्याएं ज्योंकि त्यों बनी हुई है। सरकारी आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं।

विदर्भ में औसतन प्रति व्यक्ति 5 एकड़ भूमि धारक है। कुल 23 लाख कास्तकार है। 37 लाख मजदूर है। 1 करोड़ 40 लाख ग्रामीण जनसंख्या है। नागरी जनसंख्या 66 लाख है। सूखी खेती में एक परिवार का गुजारा नहीं हो सकता। एक बैल जोड़ी के लिए 15–20 एकड़ भूमि अगर है तो ही फायदेमन्द है। छोटे किसान को बैल जोड़ी रखना संभव नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी बटवारे से भूमि ओर कम हो जाती है। इसके लिए एक अच्छा उपाय है। 4–5 परिवार मिलकर 15–20 एकड़ की सामूहिक (या सहकारी) खेती करें जिसमें एक बैल जोड़ी का खर्चा निकल जाता है। या 20 परिवार मिलकर 100 एकड़ की खेती करें, जो आत्मनिर्भर होगी। यान्त्रिक खेती (मशीनों से) संभव नहीं है। खेती के साथ–साथ जुड़े अन्य व्यवसाय कर सकते है। सही अर्थ में कृषि और कृषक का विकास यदि हम चाहते है, तो म. गांधीजी और राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की 'एग्रो टेक्नो विलेज' की संकल्पना साकार करने की आवश्यकता है।

कास्तकार के लिए risk management, contingent management का कोई प्रावधान नहीं है। इंशुरेन्स कंपनियां इधर आती ही नहीं। परिणाम यह है कि नुकसान कास्तकार को ही उठाना पडता है, उसका कर्जा बढ़ता जाता है, उसका सारा अर्थशास्त्र की बिगड़ जाता है।

ग्रामों में भी इन्फ्रास्ट्रक्चर जरुरी है। आजादी के 60 वर्ष बाद भी कृषि के बारे में बहुत कुछ करना इस देश में बाकी है। कृषि उद्योग अत्याधिक पिछड़ गया है। "भारत कृषि प्रधान देश है" यह वाक्य केवल पाठ्य पुस्तकों में रह गया है। भारत सरकार का कृषि बजट केवल 2.5 प्रतिशत है, यह दुर्भाग्य ही है। अतः देश के बजट में ही क्रांति की आवश्यकता है। महामहिम राष्ट्रपति ने कार्पोरेट क्षेत्र के प्रतिनिधियों के समक्ष भाषण में आह्वान किया है कि ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वे आगे आएं।

हर गांव में भंडारण व्यवस्था, अनाज गिरवी रखकर किसानों को आसानी से ऋण मिलने की व्यवस्था (किसान गोदाम में जितना अनाज रखता है, एवज में कुछ ऋण) होना जरूरी है। देश के सारे 6 लाख 40 हजार गांवों में ये सुविधायें हो क्योंकि मूल्य दर चढ़ते उतरते रहते हैं। अच्छी दर मिलने तक खाद्यान्न गोदामों में सुरक्षित रहेगा।

आज स्थिति यह है कि सबका पेट भरनेवाला अन्नदाता किसान ही मरणासन्न है। 1 लाख 82 हजार किसानों की आत्महत्यायें देश के लिए गौरव की बात निश्चित ही नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में पैकेज लागू हुआ केवल 44 लाख किसानों को जिन्होंने किसी ना किसी बैंक से ऋण लिया है। बचे हुए 80 लाख किसान (किसी भी बैंक से ऋण न लेने वाले) तो कहीं हिसाब में ही नहीं है। तो अब समय आ गया है कि किसानों का सबलीकरण किया जाएं। देश की अर्थनीति किसान केंद्रित बनायी जाए। तभी हर गांव खुशहाल होगा। इसी स्वदेशी मंत्र से देश आत्मनिर्भर बनेगा। ❑

(लेखक पूर्व उपकुलपति डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय एवं वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञ हैं।)

विदर्भ में संपन्न कार्यक्रम की एक झलक

पथ नाट्य प्रतियोगिता में मंत्रमुग्ध दर्शक

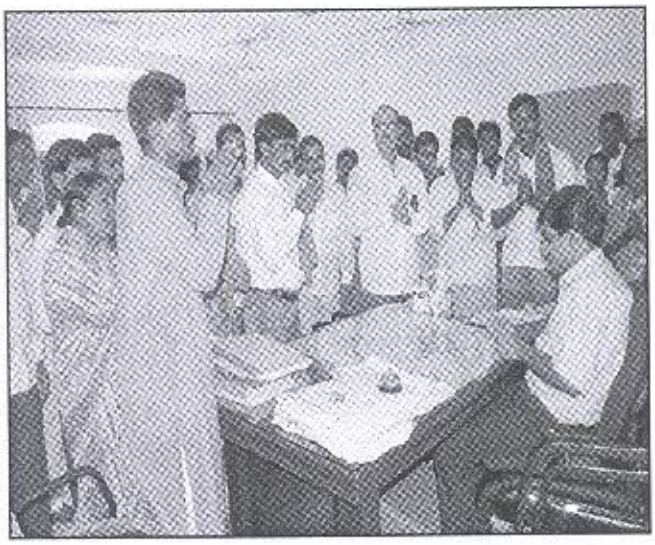

हिंगनघाट में प्रदीप नागपुरकर और
अन्य कार्यकर्ता एस.डी.ओ. को ज्ञापन देते हुए

संदस्यता संबंधी सूचना

मान्यवर,,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि "स्वदेशी पत्रिका" के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है।

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	100/–	1000/–
अंग्रेजी	100/–	1000/–

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

पता : **स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22**

विदर्भ प्रांत में स्वदेशी जागरण मंच का कार्य (1991 से 2009 तक)

■ प्रा. अविनाश साकले

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जिन विविध हथियारों का उपयोग समाज में जागृति उत्पन्न करने हेतु किया गया उनमें "स्वदेशी" का स्थान अनन्य साधारण रहा। लो. तिलक, महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों ने इस साधन का स्वातंत्र्य प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा प्रयोग किया।

1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद धीरे–धीरे इसे हम भूल गए। 1984 में हमारे शासनकर्ताओं ने एक नई अर्थनीति शुरू की। आंतरिक उदारीकरण के नाम पर परमिट, कोटा, लाईसेंस राज शुरू हुआ। इसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ता गया। विदेशी कंपनियों की भारत की अर्थनीति में घुसपैठ तेजी से शुरू हुई। बहुराष्ट्रीय कपंनियां भारत की छोटी–मझौली कंपनियों को निगलने लगी। इन हमलों के साथ–साथ गैट–डंकल प्रस्ताव, जो कई घातक रीतियां जागतिक व्यापार में लाने हेतु आ रहा था, इन सबका पुरजोर विरोध करने हेतु 22 नवंबर 1991 में नागपूर में मा. दत्तोपंत ठेंगडी जी के नेतृत्व में स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना बैठक हुई और स्वदेशी का मंत्र देश भर में फिर से गूंजने लगा।

धीरे–धीरे देश के सभी प्रांतों में स्वदेशी की अवधारणा जनमानस तक फिर से पहुंचाने का कार्य स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से होने लगा। विदभ प्रांत में गत 20 साल से इस कार्य में अपना जो योगदान रहा, उसी का संक्षेप में परिचय देने हेतु यह लेखन प्रपंच है।

- पहला राष्ट्रीयव्यापी स्वदेशी का महाअभियान 1994 को अक्टूबर से दिसंबर तक चला। विषय था "स्वदेशी और अंतर्गत सुरक्षा"। विदर्भ में नागपूर से लेकर सभी जिला स्थान, तहसील स्थान तथा सेकड़ों ग्राम और नगरों में सभाओं का आयोजन किया गया। स्वदेशी वस्तु भंडार खोले गये। लाखों लोगों ने स्वदेशी अस्मिता और सुरक्षा हेतु डंकल प्रस्ताव के विरोध में हस्ताक्षर किए।
- 23 अगस्त 1995 को नागपूर में बुनकर समस्याओं पर व्यापक बैठक हुई।
- 25 सितंबर से 2 अक्टूबर 1995 से स्वदेशी सप्ताह मनाने की परंपरा शुरू हुई।
- 15 नवंबर से 6 दिसंबर 1995 तक विदर्भ के सेवाग्राम जिला वर्धा से "पशुधन बचाओं यात्रा", श्री पी. मुरलीधर राव जी के नेतृत्व में, आंध्र प्रदेश में, रूद्रारम तक, अल कबीर कतलखाने के विरोध में निकाली गयी। वर्धा, यवतमाल, अदिलाबाद और आंध्र में बड़ी सभाएं हुई। अलकबीर परिसर में बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। पुलिस ने आंदोलन दबाने हेतु बल प्रयोग किया, फिर भी यात्रा सफल हुई।
- 15 फरवरी से 21 फरवरी 2001 तक

डॉ. केशव बलीराम हेडगेवार
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक
नागपुर (विदर्भ) कर्मभूमि

:: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ::

हिन्दू समाज में अस्मिता, तेज, स्वाभिमान के पुर्नजागरण करने हेतु सन् 1925 में विजयादशमी के अवसर पर डॉ. केशव बलीराम हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। 20 स्वयंसेवकों के साथ प्रारंभ हुए इस संगठन ने आज विशाल रूप धारण किया है। नागपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जन्मस्थली होने के कारण देशभर में लाखों स्वयंसेवकों का श्रद्धा स्थान तथा प्रेरणा स्थान बन गया है।

डॉ. हेडगेवार जी के देहांत के बाद, रेशिमबाग में ही उनका दाह संस्कार हुआ। इसी स्थान पर स्मृति मंदिर बनाया गया।

परम पूज्य डॉ. जी के देहावसान के बाद प.पू. गुरूजी 33 वर्ष तक सरसंघचालक रहे। सारे देश भर में 66 बार प्रवास कर संघकार्य को खड़ा करने का अतुलनीय कार्य उन्होंने किया।

नागपूर में बीज रूप में प्रारंभ हुआ यह संघकार्य आज देश और विश्व भर में व्याप्त हुआ है।

– श्री शिरीष तारे

नागपुर के कस्तुरचंद पार्क में भव्य स्वदेशी मेला आयोजित हुआ। 140 स्वदेशी उद्योजकों ने इसमें सहभाग लिया। लगभग 6.5 लाख दर्शकों ने इसे देखा।

- 1 जून से 15 जून 2003 तक स्वदेशी संघर्ष यात्रा का आयोजन किया गया। डॉ. रामदास आंबटकरजी के नेतृत्व में यह यात्रा विदर्भ के 11 जिलों के 80 स्थानों पर की गयी। जगह–जगह पर सभाएं संपन्न हुई। सेवाग्राम से शुरु हुयी इस यात्रा का समापन नागपूर में मा. गोविन्दाचार्य जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।
- 2 अक्टूबर 2002 को "राष्ट्रीय चेतना दिवस" मनाया गया। इसमें स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, ग्राहक पंचायत, लघु उद्योग भारती इन संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। यह प्रेरणादायी सफल आयोजन रहा।
- नागपूर स्थित धरमपेठ शिक्षण संस्था में स्वदेशी जागरण मंच के तत्वावधान में 125 शिक्षकों की कार्यशाला 4 जनवरी 2004 को संपन्न हुई। "शिक्षा में स्वदेशी जीवन दृष्टि" यह कार्यशाला का विषय था।
- 23 जुलाई 2006 को स्वदेशी भाव जागरण हेतु 350 माध्यमिक शिक्षकों की कार्यशाला नागपूर के अंधविद्यालय परिसर में संपन्न हुई। अपना विषय पढ़ाते समय भारतीय परंपरा का योगदान अधोरेखित करने वाले उदाहरण कौन से हो सकते है, इसकी चर्चा दिनभर चली कार्यशाला में हुई।
- 21 मार्च 2005 को नया पेटेंट कानून इस विषय पर एक प्रभावी परिचर्चा स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, तथा ग्राहक पंचायत के सहकार्य से आयोजित की गयी। नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद रहा।
- 6 अगस्त 2006 को स्वदेशी जागरण मंच के लगभग 60–70 कार्यकर्ताओं ने नागपूर के एक बड़े चौराहे पर कोला–पेप्सी के विरोध में भारी बारिश होते हुए भी सफल प्रदर्शन किए। मीड़िया ने उसकी अच्छी दखल ली।
- 7 दिसंबर, 2006 को "वन्देमातरम्", गान की शताब्दि के अवसर पर नागपूर के तीन प्रमुख चौराहों पर, उस परिसर में स्थित पाठशालाओं के विद्यार्थियों का सामूहिक वंदेमातरम् गान का कार्यक्रम बहुत उत्साहपूर्ण तथा अनुशासन में संपन्न हुआ। हर स्थान पर लगभग 5 से 6 हजार विद्यार्थी सम्मिलित हुए। कुल 16000 विद्यार्थियों का सहभाग रहा। एक स्थान पर पूर्व सरसंघचालक श्री सुदर्शनजी तथा मा. श्री अशोक जी सिंघल उपस्थित थे।
- 13 सितंबर 2006 को नागपूर के 70–80 खुदरा व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक "खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश" इस विषय के विरोध में संपन्न हुई।
- 28 मार्च 2007 को "SEZ" के विरोध में जनजागरण हेतु एक सभा का आयोजन किया गया। डॉ. विनायक देशपांडे का उद्‌बोधन हुआ।
- 13–14–15 जून 2008 को नागपूर में राष्ट्रीय विचार वर्ग संपन्न हुआ। इसमें विदर्भ, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाकौशल आदि प्रांतों से 125 प्रतिनिधि उपस्थित थे।

:: संत गाडगेबाबा ::

विदर्भ के इस संत ने एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में मटका (गाडगा) लेकर पूरी जिंदगीभर ग्राम–ग्राम घूमकर सफाई का अभियान चलाया और स्वच्छ परिसर और पर्यावरण की सीख गांव–गांव में दी। देवीसिंग उर्फ डेबु का जन्म विदर्भ के ग्राम कोतेगांव में इ. स. 1876 में हुआ। समाज में फैली कुरीतियां, अस्वच्छता आदि का नजदीक से निरीक्षण किया और अपनी आयु के उत्तरार्ध में ग्राम–ग्राम भ्रमण कर स्वच्छता, दारूबंदी, अंधश्रद्धा के विरोध में अभियान चलाया। ग्राम सफाई अभियान और पानी की देखभाल करना सिखाया। भजन से लोगों में जागृति निर्माण की।

20 नवंबर 1956 में अपने प्रवास के दौरान अमरावती जाते समय उनका देहांत हुआ।

ऐसे संत के नाम से संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ आज विद्यमान है। परिसर एवं पर्यावरण स्वच्छता यही इस संत के लिए उचित श्रद्धांजलि होगी।

– श्री शिरीष तारे

- 26 फरवरी 2009 को सुबह 7 से 10 बजे तक स्वातंत्र्यवीर सावरकरजी लिखित "जयोस्तुते" इस गीत के गायन की स्पर्धा संपन्न हुई। 16 पाठशालाओं के 400 विद्यार्थियों ने भाग लिया। बड़े चौराहे पर आयोजित समापन के प्रमुख कार्यक्रम में अतिथि के नाते नागपूर के पुलिस आयुक्त श्री प्रवीण दीक्षित उपस्थित थे।
- इन कार्यक्रमों के अलावा लगभग प्रतिवर्ष 1 अगस्त को तिलक पुण्यतिथि, 25 सितंबर से 2 अक्टूबर स्वदेशी सप्ताह, शरद पूर्णिमा, 12 दिसंबर को बाबू गेनू स्मृति दिन आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यह कार्यक्रम नागपूर में संपन्न होते हैं, जिला स्थान और ग्राम स्तर पर कार्यक्रम की मात्रा कम है। ●

स्वदेशी जारगण मंच, विदर्भ
विदर्भ प्रदेश – वार्षिक कार्यवृत्त : 2010–11

- 2, 3, 4 अक्टूबर 2010 को जालंधर में आयोजित राष्ट्रीय सभा में प्रांत से 25 की संख्या उपस्थित रही।
- 9 अक्टूबर 2010 को महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में महानगर पालिका पाठशाला में पढ़ने वाले सेवाबस्ती के निवासी 100 विद्यार्थियों ने खादी वस्त्र खरीदा। सांकेतिक स्वरूप में स्वदेशी अपनाने वाले बच्चों को जैविक खाद में लगाया हुआ तुलसी एवं गुलाब का एक एक पौधा भेंट किया गया। यह खाद भी 70 छात्रों के गुट ने पाठशाला परिसर में ही अधिवक्ता श्री अविनाश काले के नेतृत्व में 6 महीने सतत् कार्यरत रहकर तैयार किया था। राष्ट्रीय सभा के कारण यह कार्यक्रम विलंब से संपन्न हुआ।

अखिल भारतीय संगठक मा. कश्मीरीलाल जी का प्रवास

- **23 अक्टूबर 2010 (शरद पूर्णिमा):** श्री कश्मीरीलाल जी की उपस्थिति में शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 18 महिलाओं सहित कुल 82 की उपस्थिति रही। श्री कश्मीरीलाल जी का उद्‌बोधन हुआ।
- **24 अक्टूबर, वर्धा :** प्रवास के दरम्यान संचालन समिति तथा लघु उद्योजकों की बैठकें हुई। ओबामा भारत भेंट के छिपे कार्यक्रम पत्रिका का विरोध करने का निश्चित किया गया।
- **25 अक्टूबर 2010, हिंगनघाट :** व्यापारी, महिलाएं, प्रतिष्ठित नागरिक, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, पाठशाला छात्र–छात्राओं की बैठकें आयोजित की गई। तहसील स्थान की इस महिला बैठक में 56 महिलाएं उपस्थित थी। 26 अक्टूबर खामगांव में मा. कश्मीरीलाल जी के प्रवास में प्रतिष्ठित नागरिकों की बैठक आयोजित की गई। 35 की उपस्थिति रही।

प्रस्तुति : प्रा. अजय पत्की

नागपुर – कार्यवृत्त

- **31 अक्टूबर 2010 :** इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, नागपुर शाखा के सभागमर में "Role of Professionals in Enriching India" इस विषय पर मंच के राष्ट्रीय सहसंयोजक श्री एस. गुरुमूर्ति जी

:: राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ::

विदर्भ में जन्मे और पले बढ़े राष्ट्रसंत वं. तुकडोजी महाराज क्रांतदर्शी, देशभक्त और साहित्यिक थे। स्वातंत्र्यपूर्व काल से समाज प्रबोधन में व्यस्त इस महामानव ने स्वातंत्र्योत्तर काल में स्वराज्य को सुराज्य में बदलने हेतु ग्रामगीता लिखी। वं. तुकडोजी महाराज जी ने पूरा जीवन समाज प्रबोधन में समर्पित किया। उन्होंने अपने कार्यकाल में सारे देश का भ्रमण किया। हर दिन नये ग्राम में जा कर भजन, प्रवचन द्वारा जनजागृति यह कार्यक्रम अविरत शुरू रखा।

उनका प्रबोधन का क्षेत्र बहुत ही व्यापक था। ग्राम, कृषि, आरोग्य, आहार, पशु संवर्धन से लेकर मानसशास्त्र, राज्यशास्त्र, व्यवहार, अध्यात्म, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि सभी विषयों का इसमें अंतर्भाव है। विदर्भ के अमरावती जिले में मोझरी यह ग्राम इनका मूल कार्यक्षेत्र रहा। वे कहते थे कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात स्वर्ग प्राप्ति की बाते सिखाने की बजाय, जीवित होते हुए इस देश को स्वर्ग बनाने की सीख देने की आवश्यकता है। ऐसे संत के कार्य के प्रति आदर और श्रद्धा दर्शाने नागपूर विद्यापीठ का नाम राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर रखा गया। इस राष्ट्रसंत की जीवनधारा भारतीय समाज को प्रेरणा देती रहेगी।

प्रयाग में 1965 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। उसमें राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज सम्मिलित हुए थे। इस महापुरुष का देहांत 1965 में हुआ।

– श्री शिरीष तारे

का भाषण हुआ। चार्टर्ड अकाउंट्स, कंपनी सचिव, कॉस्ट अकाउंट्स, डॉक्टर्स आदि की 76 उपस्थिति रही। कार्यकर्ता तथा अन्य उपस्थिति कुल 126 की रही।

- **6 नवंबर 2010** : अमरीकी राष्ट्राध्यक्ष श्री बराक ओबामा के भारत प्रवास प्रारंभ दिन को नागपुर में डॉ. मुंजे चौराहे पर भारी प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बनाए गए विदेशी कंपनियों के प्रतिनिधियों के पुलिस ने जब्त किया। 225–250 नागरिकों के सहभाग से मोर्चा निकाला गया। महिलाओं की संख्या उल्लेखनीय रही। लक्ष्मीपूजन का दिन होने से श्री लक्ष्मी जी तथा भारतमाता के छायाचित्रों के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर महिलाओं ने संपूर्ण आर्थिक स्वाधीनता की प्रार्थना की। दूसरे दिन नगर के सारे समाचार पत्रों ने छायाचित्र सहित समाचार प्रकाशित किया। जी, स्टार तथा स्थानीय वाहिनियों ने समाचारों में प्रदर्शन को काफी समय तक दिखाया।

  नागविदर्भ चेंबर ऑफ कामर्स के श्री नीलेश सूचक, विदर्भ संगठन के श्री प्रभाकर फुलबांधे व श्री अंबादास पाटील, हाथठेला व्यापारी संघ श्री मदन थूल, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स के बी.सी. भरतिया, विदर्भ रूरल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के श्री फारूख भाई, खुदरा किराना व्यापारी संघ तथा अन्य संगठनों के प्रतिनिधि मोर्चे में सहभागी हुए। संचालन समिति से भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, राष्ट्र सेविका समिति, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, सहकार भारती, विद्यार्थी परिषद्, अधिवक्ता परिषद् के कार्यकर्ता सहभागी हुए।

- **हिंगनघाट में विदेशी निवेश विरोधी मोर्चा** : इस छोटे तहसील स्थान पर मंच की ओर से भारतीय युवा संस्कार परिषद् के सहयोग से मोर्चे का आयोजन किया गया। गांधी चौक से प्रारंभ हुआ यह मोर्चा गाँव के प्रमुख मार्ग से चलकर उपविभागीय अधिकारी कार्यालय के प्रांगण में समाप्त हुआ। 100–125 नागरिकों की उपस्थिति में श्री देवेन मोटवानी, श्री जेठानंदजी राजपूत, श्री प्रदीप नागपुरकर तथा प्रांत संगठक श्री राजीव क्षीरसागर ने उपविभागीय अधिकारी श्री संजय दैने को ज्ञापन सौंपा। चार समाचार पत्रों ने छायाचित्र सहित समाचार प्रकाशित किये।
- **श्री राजीव दीक्षित को श्रद्धांजलि**: आजादी बचाओ आंदोलन के जुझारू कार्यकर्ता श्री राजीव दीक्षित को श्रद्धांजलि अर्पण करने का कार्यक्रम दिनांक 8 नवम्बर को संपन्न हुआ। राष्ट्रीय परिषद् सदस्य श्री धनंजय भिडे तथा प्रांत विचार मंडल प्रमुख प्रा. अविनाश साकले ने स्वर्गीय राजीव दीक्षित के जीवन तथा स्वदेशी आंदोलन में योगदान को उजागर किया।
- **बाबूगेनू स्मृति दिवस** : 12 दिसंबर को प्रातः 9 से 12 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विचार मंडल प्रमुख प्रा. अविनाश साकले ने शहीद बाबूगेनू के जीवनकार्य पर उद्‌बोधन किया। कार्यक्रम का संचालन मंच के नागपुर महानगर संयोजक श्री आशुतोष पाठक ने किया। इस अवसर पर स्वदेशी अध्ययन तथा अनुसंधान परिषद् की औपचारिक स्थापना की गई। नागपुर विश्वविद्यालय के व्यवस्थापन शास्त्र विभाग प्रमुख डॉ. विनायक देशपांडे ने अध्यक्षता की। प्राचार्य योगानंद काले ने स्वदेशी अध्ययन तथा अनुसंधान परिषद् के स्थापना की भूमिका स्पष्ट की।

  'भारत के कर प्रणाली का स्वदेशी पर्याय' इस विषय पर चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री अतुल देशमुख ने दृकश्राव्य पद्धति का विषय प्रस्तुत किया। 72 की कुल उपस्थिति में अर्थशास्त्र विषय को विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाने वाले शिक्षक, शोध विद्यार्थी, व्यवस्थापन शास्त्र विषय के सलाहकार आदि की संख्या 50 के आसपास रही। मुंबई के श्री रवींद्र महाजन विशेष रूप से उपस्थित रहे।
- **9 जनवरी 2011 पुस्तक प्रकाशन**: इंदौर के ज्येष्ठ कार्यकर्ता एवं मा. दत्तोपंतजी के सहकारी श्री रमेश तांबे द्वारा लिखित 'हिंदुत्व का ही आग्रह क्यों' इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया। 52 की उपस्थिति में हुए इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार श्री दिगंबर (मामासाहब) घुमरे का 'स्वदेशी की प्रासंगिकता' इस विषय पर प्रबोधन हुआ।
- **12 जनवरी 2011 (अ) युवा सम्मेलन**: स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर युवा सम्मेलन आयोजित किया गया। विवेकानंद फाउंडेशन (अंतरराष्ट्रीय) के सचिव श्री मुकुल कानिटकर का 'वर्तमान राष्ट्रीय चुनौतियों के समाधान में युवाओं का योगदान' इस चर्चा सत्र आयोजित किया गया। लगभग एक घंटे के भाषण में उन्होंने युवाओं को चुनौतियों से अवगत कराया। उसके पश्चात्

30 मिनट तक युवाओं ने प्रश्नोत्तरी के कार्यक्रम में अनेक प्रश्न किए। श्री मुकुलजी ने सभी प्रश्नों के यथोचित उत्तर दिये। इस कार्यक्रम में केवल व्यावसायिक महाविद्यालयों के छात्र–छात्राओं को निमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम का प्रास्ताविक एवं आभारत प्रदर्शन मंच के नागपुर महानगर संयोजक श्री आशुतोष पाठक ने किया।

(ब) महिला सम्मेलन : भारतीय स्त्री शक्ति इस संगठन के सहयोग से श्री मुकुल कानिटककर का 'स्वदेशी – वर्तमान परिस्थिति में अर्थ, उपयोगिता एवं अनिवार्यता' इस विषय पर प्रबोधन कार्यक्रम संपन्न हुआ। महिलाओं के इस कार्यक्रम में लगभग 120 महिलाएं उपस्थित रही। अबोधन अत्यंत प्रभावी रहा। स्वदेशी विदेशी वस्तुएं एवं निर्माताओं की सूची वितरित की गई।

- **28 जनवरी 2011** : रत्नागिरी (कोंकण–महाराष्ट्र) के पर्यावरण एवं निसर्ग साधक तथा इस विषय के लेखक श्री दिलीप कुलकर्णी का 'पर्यावरण रक्षण की स्वदेशी परंपरा' इस विषय पर संबोधन आयोजित किया। एक घंटे के व्याख्यान में 110 की उपस्थिति रही, जिसमें 50 महाविद्यालयीन छात्र–छात्राएं थी।
- **6 फरवरी 2011** : महाराष्ट्र प्रांत संयोजक प्रा. अजय पत्की के प्रथम प्रवास के अंतर्गत कार्यकर्ता संवाद एवं राष्ट्र सेविका समिति द्वारा आयोजित मकरसंक्रमण कार्यक्रम के निमित्त आयोजित स्वदेशी वस्तु प्रदर्शनी तथा मेले में उनकी उपस्थिति रही। विदर्भ प्रांत संयोजक पद पर नियुक्ति के पश्चात् श्री अमोल पुसदकर का वर्धा, सेवाग्राम, हिंगनघाट इन स्थानों पर प्रवास हुआ।
- **11 फरवरी 2011** : नंदीखेड़ा, पवनार (जिला वर्धा) इस स्थान पर माघ शु. नवमी को यात्रा का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। इस वर्ष नूतनीकृत घाट पर धाम नदी पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। वर्धा के श्री हेमंत महाराज पाचखेडे की संकल्पना रही। 250 के आसपास श्रद्धालुओं ने नदीपूजन एवं दीपदान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विहिप के प्रांत संगठन मंत्री श्री विजय माताडे, मंत्री प्रा. अजय निलदावार प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। प्रा. अजयजी का संबोधन हुआ। आयोजन हेतु प्रांत संयोजक श्री अमोल पुसदकर ने 3 बार पवनार में प्रवास किया। नागपुर से स्वदेशी जागरण मंच के 21 कार्यकर्ता सहभागी हुए। समाचार पत्रों ने छायाचित्र सहित वृत्त प्रकाशित किया।

प्रस्तुति : आशुतोष पाठक

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

हमारा पता है :–

संपादक

स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

सेवाग्राम से शोधग्राम तक एक यात्रा

(डॉ. अभय बंग और डा. राणी बंग के साथ)

डॉ. अभय बंग और डॉ. श्रीमति राणी बंग ने 1978 में विवाहित होने के बाद श्री जयप्रकाश नारायण के आह्वान से प्रेरणा लेकर वर्धा (महाराष्ट्र) के निकट कान्हापुर ग्राम में कार्य करने का निश्चय किया। ग्रामीणों को घातक बीमारियों से बचाने तथा साथ ही गांव का चेहरा बदलने के स्वप्न के साथ उन्होंने वहां 3 साल काम किया, हर ग्रामवासी को स्वास्थ्य सेवा प्रदान की।

■ पराग और अरुंधती पांढरीपांडे

(SEARCH) सोसायटी फॉर एज्युकेशन एंड एक्शन एंड रिसर्च इन कम्यूनिटी हेल्थ, यह अब एक अतिविशाल विश्वविख्यात संस्थान है जो आदिवासियों के स्वास्थ्य की चिंता तथा अनेक बीमारियों के संबंध में शोधकार्य करता है। यह मात्र अस्पताल ही नहीं, वरन्, दाई, पुजारी तथा ग्राम से स्वास्थ्य दूतों के प्रशिक्षण का केंद्र भी है, जो उन्हें स्वयं के ग्राम में वनवासी ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना सिखाता है।

डॉ. अभय बंग और डॉ. श्रीमति राणी बंग ने 1978 में विवाहित होने के बाद श्री जयप्रकाश नारायण के आह्वान से प्रेरणा लेकर वर्धा (महाराष्ट्र) के निकट कान्हापुर ग्राम में कार्य करने का निश्चय किया। ग्रामीणों को घातक बीमारियों से बचाने तथा साथ ही गांव का चेहरा बदलने के स्वप्न के साथ उन्होंने वहां 3 साल काम किया, हर ग्रामवासी को स्वास्थ्य सेवा प्रदान की।

उन्होंने इस तथ्य को भी समझा कि मात्र स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने से ग्रामवासियों की समस्याएं नहीं सुलझेगी। ऐसी बीमारियां जिनसे भारतीय जन पीड़ित है, के बारे में शोधकार्य करने वाले वैज्ञानिक व डॉक्टर विदेशी है, न कि भारतीय! अधिकांश भारतीय डॉक्टर्स तो देहातों में गये ही नहीं, और जो गये उनके लिए वहां शोधकार्य करने के लिए उचित सुविधाएं नहीं थी। तब दम्पति ने जनस्वास्थ्य के शोधकार्य हेतु उचित प्रशिक्षण किया।

इस डॉ. दम्पति ने गड़चिरोली यह विदर्भ का सर्वाधिक उपेक्षित जिला कार्य के लिए चुना। इस में 60 प्रतिशत वनक्षेत्र है और 40 प्रतिशत जनसंख्या अंधविश्वास में डूबे आदिवासियों की है। 1986 में ग्रामवासियों ने उन्हें एक पुराना तेंदूपत्ता गोदाम उपलब्ध कराया जिसमें प्राथमिक शोध केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्र, संगणक केंद्र प्रस्थापित हुआ। इस तरह "सर्च" का बोर्ड अस्तित्व में आया।

उन्होंने गांव गांव जाकर यह खोजन की कोशिश की कि लोग अस्पताल जाने से क्यों कतराते हैं। चर्चाओं के उपरांत इस निष्कर्ष पर आये कि अस्पताल एक आदिवासी देहात जैसा दिखना चाहिए।

फिर मां दन्तेश्वरी दवाखाना का निर्माण किया, स्थान का नामकरण हुआ "शोधग्राम"। यहां प्रतिवर्ष मेला आयोजित किया जाता है, उसमें 50–60 गांवो से लोग आते हैं और आदिवासियों की संसद स्वास्थ्य संबंधी अहम मुद्दों का निर्धारण करती है, तदनुसार उनके समाधान हेतु सर्च उन्हें स्वीकार करता है। मलेरिया, नवजात शिशु की मृत्यु, पुरुषों की बीमारियां, स्त्रीरोग,

(शेष पृष्ठ 25 पर)

:: डॉ. बाबासाहेब अंबेडकरजी ::

:: दीक्षा भूमि ::

14 अक्टूबर 1956 के विजयादशमी के दिन नागपूर में "धम्मचक्र प्रवर्तन" हुआ। डॉ. बाबासाहेब अंबेडकरजी ने अपने नेतृत्व में स्वयं बुद्ध धम्म को अपनाकर और लाखों अनुयायियों को बुद्ध के धम्म की दीक्षा स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर तथा उन्हें धम्म दीक्षा देकर एक इतिहास रचा। यह कार्यक्रम नागपूर में जिस स्थान पर संपन्न हुआ उसे आज सब लोग "दीक्षाभूमि" नाम से जानते है। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के अवसर पर 20 लाख श्रद्धालुओं ने इसमें भाग लिया। तबसे प्रतिवर्ष यहां विजयादशमी के दिन लाखों बौद्ध बंधू धम्मचक्र प्रवर्तन दिन मनाते हैं।

आज नागपूर की दीक्षा भूमि पर 5000 व्यक्ति आराम से बैठ सके ऐसा विशाल स्तूप खड़ा है। इस भव्य स्तूप की ऊंचाई दुनिया के स्तूपों में सबसे ज्यादा यानी 120 फुट है। इस स्तूप में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी की अस्थियां चांदी के कलश में स्थापित हैं। भारत के और दुनिया भर के श्रद्धालु इसका दर्शन करने नागपूर आते हैं। नागपूर नगरी में दीक्षाभूमि एक प्रमुख श्रद्धा तथा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।

विदर्भ के औद्योगिक विकास की समीक्षा

विदर्भ में जितने भी जिलों का समावेश है, उन सभी की स्वयं की एक औद्योगिक पहचान है। हथकरघा (बुनाई) नागपूर के साथ जुड़ा हुआ है। नागपूर की मॉडल मिल, एम्प्रेस मिल, इसका ठोस परिचायक है। ऑरेंज सिटी नाम से नागपूर जिला विश्वभर में सुपरिचित है। वाशिम "कपास का मँचेस्टर" के नाम से पहचाना जाता था। चंद्रपुर खनिज संपदा एवं वनसंपदा से बहुचर्चित था।

■ किशोर काले

विदर्भ की भूमि "राजभूमि" नाम से पहचानी जाती थी। विदर्भ की औद्योगिक परंपरा भी गौरवशाली है। भारत में जितने भी राज्य सम्मिलित हैं, इनमें महाराष्ट्र प्रगत राज्य है। इस औद्योगिक प्रगत राज्य का विदर्भ एक विभाग है। किंतु यह विभाग औद्योगिक विकास के संदर्भ में बहुत ही पीछे है। विदर्भ निवासियों के लिए यह गंभीर विषय है।

किसी विभाग की औद्योगिक प्रगति के लिए जितनी आवश्यक सुविद्याएं होना जरूरी है, वे सभी विदर्भ के पास उपलब्ध है।

विदर्भ में जितने भी जिलों का समावेश है, उन सभी की स्वयं की एक औद्योगिक पहचान है। हथकरघा (बुनाई) नागपूर के साथ जुड़ा हुआ है। नागपूर की मॉडल मिल, एम्प्रेस मिल, इसका ठोस परिचायक है। ऑरेंज सिटी नाम से नागपूर जिला विश्वभर में सुपरिचित है। वाशिम "कपास का मँचेस्टर" के नाम से पहचाना जाता था। चंद्रपुर खनिज संपदा एवं वनसंपदा से बहुचर्चित था। बीडी उद्योग का भंडारा एवं गोंदिया जिला में प्रमुख स्थान है। उद्योग संस्कार से विदर्भ विभाग परिचित है। विदर्भ का कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र को पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल प्रदान करने के लिए समर्थ है। कपास, सूर्यफूल (सोयाबीन) मूंगफली आदि विदर्भ के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उद्योग निर्माण कार्य के लिए भूखंड की आवश्यकता होती है।

विदर्भ के सभी जिलों में उद्योग निर्माण के लिए भूखंड आवंटित है। ईंधन एवं ऊर्जा स्रोत "उद्योग जगत की प्राणवायु" समझी जाती है। यह प्राण वायु विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कोयला, मॅग्नीज, लोह यह सभी खनिज संपदा विदर्भ के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

आवागमन एवं संपर्क सेवा औद्योगिक प्रगति का आवश्यक स्रोत है। विदर्भ में रेलवे, वायु, सड़क मार्ग उपलब्ध है। संपर्क सेवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। किंतु यह सभी आवश्यक सुविधाएं विदर्भ विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के पश्चात भी विदर्भ विकास की दर इतनी धीमी क्यों है? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है।

विकास किसी दूसरे राष्ट्रों से आयात करने की वस्तु नहीं है। विकास की प्रेरणा होती है। वह प्रेरणा निर्माण होने के लिए अनुकूल औद्योगिक पर्यावरण की आवश्यकता होती है। औद्योगिक पर्यावरण का अभाव, यह विदर्भ की मुख्य समस्या है। औद्योगिक पर्यावरण तैयार करने का दायित्व सत्ताधारी पक्ष, विरोधी पक्ष, सामाजिक एवं औद्योगिक संस्थाएं, जनता के सहयोग तथा प्रबल राजकीय इच्छा शक्ति पर निर्भर होता है।

औद्योगिक पर्यावरण राज्य की आर्थिक एवं औद्योगिक नीति पर निर्भर होता है। महाराष्ट्र राज्य की औद्योगिक नीति विदर्भ विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। महाराष्ट्र शासन की कर प्रणाली,

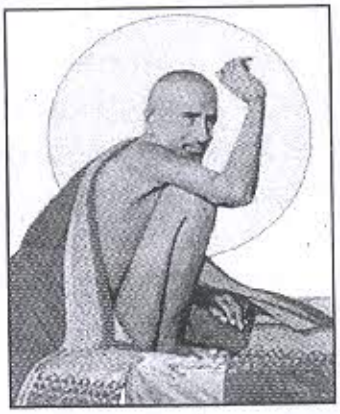

:: संतश्रेष्ठ गजानन महाराज ::

विदर्भ के शेगांव स्थान पर मंदिर लाखों श्रद्धालुओं का प्रेरणा स्थान

बाजार प्रणाली, विदर्भ विभाग में औद्योगिक पर्यावरण तैयार करने की दृष्टि से अनुकूल होनी चाहिए। विदर्भ के बाहर के उद्योजक उद्योग स्थापित करने के लिए आकर्षित होने चाहिए। महाराष्ट्र राज्य की औद्योगिक नीति उद्योजकों को आकर्षित करने में समर्थ नहीं है। यह वस्तुस्थिति है।

विदर्भ में बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। किंतु बिजली की दर बहुत ज्यादा है। जलप्रदाय दर भी बहुत ज्यादा है। विदर्भ में औद्योगिक लाइसेन्स प्रणाली सरल नहीं है, बहुत जटिल है।

विदर्भ की विपणन व्यवस्था भी सुसंगठित नहीं है। विदर्भ के उद्योग की लाभ क्षमता कम होने के कारण वित्तीय संस्थाएं वित्त प्रदान करने के लिए आगे नहीं आती है। विदर्भ की बिजली, खनिज संपत्ति का उपयोग विदर्भ के विकास के लिए नहीं हो रहा है। ये सभी चीजें

विदर्भ के बाहर जा रही है। विदर्भ में औद्योगिक विकास प्रक्रिया प्रभावपूर्ण होने के लिए विशेष प्रकार का मॉडल तैयार होना चाहिए। विदर्भ का वर्धा जिला राष्ट्रीय स्तर पर "महात्मा गांधी" के नाम से जाना जाता है। इस वर्धा में एमगिरी नामक संस्था है। 2009 में इसे संस्था स्वायत्तता का दर्जा प्राप्त हुआ है। ग्रामीण विभाग का औद्योगिकरण इस संस्था का उद्देश्य है। इस प्रकार की संस्था विदर्भ विभाग के हर गांव में स्थापित होना जरूरी है।

इस प्रकार की संस्थाओं के साथ स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय, स्व. नानाजी देशमुख द्वारा प्रेरित अंत्योदय संस्था का निर्माण होना जरूरी है तथा विद्यापीठ महाविद्यालय अनुसंधान संस्था, वित्त संस्थायें इसी संस्था से जुड़ी हुई होनी चाहिए। ग्रामीण एवं शहर की बौद्धिक संपदा, युवा शक्ति, राजकीय शक्ति इसी संस्था से जुड़ी होनी चाहिए। सभी के उचित औद्योगिक संस्कारों के लिए ऐसी संस्थाओं की विशेष जरूरत होती है।

इस प्रकार की शक्ति महाराष्ट्र शासन को विदर्भ विकास के लिए साध्य करनी होगी। इसी शक्ति से विदर्भ में कृषि क्षेत्र– कृषि आधारित उद्योग, संतरा उत्पादन – इस पर आधारित औद्योगिक प्रक्रिया कपास–सूती कपड़ा यह प्रक्रिया कड़ी मजबूत हो सकती है।

विदर्भ की साधन संपत्ति का 50 प्रतिशत हिस्सा विदर्भ विकास के लिए उपयोग में आना चाहिए यही विदर्भ की जनता की मांग है। यह मांग यदि पूरी नहीं हुई तो विदर्भ महाराष्ट्र से विभक्त होना चाहिए और विदर्भ को स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्राप्त होना चाहिए।

आज विदर्भ का पूर्वी हिस्सा नक्सालवादी समस्याओं में उलझा हुआ है। विदर्भ की सारी शक्तियां एकजुट हो कर इस विभाग की प्रगति के लिए आगे आना जरूरी है। यही इस समस्या का सही उपाय है।

विदर्भ विभाग का औद्योगिक विकास का मॉडल ऐसा होना चाहिए कि उस मॉडल की मदद से विदर्भ के परंपरागत व्यवसाय का विकास होना चाहिए और नये उद्योग स्थापित हों। विदर्भ का औद्योगिक विकास प्रदूषण से मुक्त होना चाहिए। इस व्यापक मॉडल के आधार पर विदर्भ के औद्योगिक विकास को सही दिशा प्राप्त हो सकती है। उचित औद्योगिक संस्कार की निर्मिति हो सकती है। ग्रामीण उद्योग, शहरी उद्योग, परंपरागत उद्योग, नये उद्योग, छोटे उद्योग, बड़े उद्योग एकसाथ विकसित हो सकते हैं।

इस विकास प्रक्रिया का अंतिम उद्देश्य "महत्तम सामाजिक कल्याण" होना चाहिए। इसी दिशा में संपूर्ण विकास प्रक्रिया परिवर्तित होनी चाहिए। अन्त्योदय के लिए यही विकास प्रक्रिया बहुत ही प्रभावशाली हो सकती है। ❑

(पृष्ठ 23 का जारी. . .)

सेवाग्राम से शोधग्राम तक. . .

सिकलसेल्स आदि बीमारियां पहचानकर उनका अध्ययन "सर्च" ने किया। डॉ. राणी ने पाया की देहातों में स्त्रीरोगों की मात्रा अत्याधिक है। इसकी जानकारी पाने वे वॉशिंग्टन नेशनल लाईब्रेरी गयी, परंतु ध्यान में आया कि ग्रामीण महिलाओं की बीमारियों के बारे में अब तक कोई अध्ययन ही नहीं हुआ है। अब सर्च द्वारा एक शोधकार्य हाथ में लिया गया।

नमूने के तौर पर दो गांव चुनकर उनकी सारी महिलाओं की जांच की गया और अध्ययन कर यह शोध विश्वविख्यात मेडिकल जर्नल "लान्सेट" में 1989 में प्रकाशित किया गया कि भारत की ग्रामीण महिलाओं में स्त्रीरोगों की मात्रा कितनी अत्याधिक है।

विश्वभर में यह प्रथम अध्ययन सिद्ध हुआ और इससे महिला स्वास्थ्य अध्ययन में लहरें उठी। इसे दशक के विशेष अध्ययन के रूप में अमेरिका में सम्मानित किया गया।

गडचिरोली जिले में उन दो गांवों के शोधकार्य के कारण ही बाद में "कैरो" में विश्व जनसंख्या कार्यक्रम को बदलकर महिला प्रजनन स्वास्थ्य पर जोर दिया गया। नवजात शिशुओं की मृत्यु के बारे में सर्च में शोध प्रारंभ हुआ। इसके लिए जिम्मेदार 18 कारणों में कुपोषण, न्यूमोनिया और भ्रष्टाचार भी है ऐसा उनके ध्यान में आया।

गड़चिरोली में 1988 में जब नवजात शिशुओं की मृत्यु के विषय पर कार्य आरंभ हुआ तब नवजात शिशु मृत्युदर आय.एम.आर. (इन्फन्ट मॉर्टेलिटी रेट) 121 थी जो 2000 में 30 पर उतर गयी।

डॉ. अभय बंग का कहना है कि शोध में प्रचण्ड शक्ति है और विश्वभर में इसके परिणामों को अनुभव किया जा सकता है। 21वीं सदी में ज्ञान और सूचना ही संपदा और शक्ति के स्रोत हैं। समाज कार्य और समाज सेवा के स्वरूप में अत्याधिक परिवर्तन आया है।

उनका मानना है कि एक स्थान पर रोगी का उपचार करने की बजाय सामाजिक स्वास्थ्य पर शोध से करोड़ों लोगों तक लाभ पहुंचता है और इस तरह सामाजिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान हो सकता है। ❑

प्रस्तावित ताप विद्युत केंद्रों से विदर्भ का विकास होगा या विनाश?

विदर्भ में 80–85 प्रतिशत भूमि बिना सिंचन सुविधा की है। ऐसे खेतों में ली जानेवाली रबी फसल पूरी तरह से भूमि एवं हवा की आर्द्रता पर निर्भर होती है। प्रकल्पों की वजह से बढ़ने वाली गर्मी का विपरीत परिणाम इस कृषि पर होगा। दूसरी फसल लेना महज एक सपने जैसा ही होगा।

■ धनंजय भिड़े

विदर्भ वैधानिक विकास महामंडल द्वारा प्रसिद्ध रपट के अनुसार विदर्भ में 43 ताप विद्युत प्रकल्पों का आगमन होने जा रहा है। इनमें से कोराड़ी, खापरखेड़ा, पारस, चंद्रपुर इन चार विद्यमान प्रकल्पों के विस्तार की योजना है। शेष 39 प्रकल्प नये होंगे। इनमें से 34 प्रकल्प निजी कंपनियों के है।

(1) उपरोक्त प्रस्तावित प्रकल्पों के लिए कुल 18140 हेक्टर (भूमि) जमीन अधिग्रहित की गई है। उच्च दबाव के प्रवाह की वजह से 60,000 हेक्टर जमीन प्रभावित होगी।

(2) बिजली निर्माण के लिए बड़े प्रमाण पर पानी की आवश्यकता है। प्राथमिक आकलन के अनुसार 993 दशलक्ष घनमीटर अर्थात 35 टी.एम.सी. पानी की जरूरत होगी। इससे 1.5 से 2 लाख हेक्टर सिंचाई क्षेत्र कम होने की संभावना है।

(3) उपरोक्त प्रकल्पों को नियमित तौर पर 5 लाख 50 हजार मेट्रिक टन कोयला चाहिए जिसका अधिकांश हिस्सा (कोयला) विदेश से आयात किया जाना जरूरी है।

(4) इतने प्रमाण में कोयले के जलने से नित्य करीब 30 प्रतिशत अर्थात 1 लाख 65 हजार मैट्रिक टन राख बनेगी।

(5) अधिकांश प्रकल्प "सेझ" अर्थात् विशेष आर्थिक क्षेत्र में होने से निर्मित बिजली की दर पर सरकार अपना उत्पादित कुल बिजली में से 67 प्रतिशत निर्मिती विदर्भ के प्रकल्पों द्वारा होती है। फिर भी बिजली कटौती की सबसे अधिक मार विदर्भ को सहनी पड़ रही है। नये सिरे से प्रस्तावित विद्युत प्रकल्पों की वजह से विदर्भ का बिजली संकट दूर होने से किसी भी प्रकार की मदद नहीं होगी, क्योंकि यह बिजली सेझ और अन्य बड़े शहरों के उद्योगों को दी जायेगी।

इन प्रकल्पों की वजह से विदर्भ पर पर्यावरण प्रदूषण के भीषण संकट का खतरा मंडरा रहा है।

कृषि, कृषक (किसान) और सिंचन पर होने वाला दुष्प्रभाव

(1) विदर्भ में कुल 52 लाख हेक्टर कृषि योग्य भूमि है, इसमें से मात्र 4 से 5 लाख हेक्टर (8 से 10 प्रतिशत) भूमि सिंचित है। विदर्भ की सिंचाई अनुशेष दूर करके सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने की बजाए 35 टी.एम.सी. पानी विद्युत निर्माण हेतु उपयोग में लाने से सिंचाई क्षेत्र में 1.5 से 2 लाख हेक्टर की कमी होने की संभावना है।

(2) प्रकल्प में प्रयुक्त कोयले के ज्वलन से 15000 किलो कैलरी (ताप ऊर्जा) का निर्माण होकर इसमें से 30–35 प्रतिशत प्रत्यक्ष विद्युत निर्माण के काम में आयेगी और शेष ऊर्जा पर्यावरण में घुलमिलकर तापमान में 1.5 से 2 अंश सेल्सिअस तक की बढ़त होगी।

विदर्भ में 80–85 प्रतिशत भूमि बिना सिंचन सुविधा की है। ऐसे खेतों में ली जानेवाली रबी फसल पूरी तरह से भूमि एवं हवा की आर्द्रता पर निर्भर होती है। प्रकल्पों की वजह से बढ़ने वाली गर्मी का विपरीत परिणाम इस कृषि पर होगा। दूसरी फसल लेना महज एक सपने जैसा ही होगा।

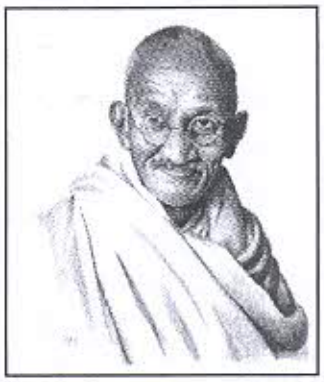

:: राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ::

वर्धा जिला के सेवाग्राम में आश्रम ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध में देशव्यापी आंदोलन चलाया

इस वजह से किसानों के उत्पादन में भारी कमी होगी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भारतीय कृषि के सामने 20 से 40 प्रतिशत उत्पादन में कमी होने की चुनौती पहले से ही मौजूद है। यह बात केंद्रीय मंत्रालय के अध्ययन में होने पर भी विद्युत प्रकल्पों से पर्यावरण में बढ़ने वाली गर्मी किसान को झुलसाकर रख देगी।

(1) कोयले के जलने से प्रतिदिन 6 से 9 लाख टन कर्बाम्ल वायु का उत्सर्जन होगा।

(2) प्रकल्प से प्रतिदिन निर्माण होने वाली 1 लाख 65 हजार मैट्रिक टन राख

(शेष पृष्ठ 31 पर)

प्राचीन विदर्भ

व्यापारी दृष्टि से गत 1500 वर्ष में विदर्भ भारत का दक्षिण भारतीय अर्थ केंद्र था, जहां से संपूर्ण दक्षिण भारत का अर्थ व्यवहार चलता था। आजका जो महाराष्ट्र है वह क्षेत्र की विदर्भ में ही अंतर्भूत था। यहां की वैदर्भी रीति वाडमय की पूर्णावस्था थी। हमारा विदर्भ गत 2000 वर्षों से दक्षिण भारत क्षेत्र में अग्रेसर रहा।

■ श्रीपाद केशव चितले

विदर्भ यह भूक्षेत्र अत्यंत प्राचीन काल से सुप्रसिद्ध है। प्रागैतिहासिक कालखंड के संदर्भ में इस क्षेत्र में करीब 2 लाख 50 हजार वर्ष पूर्व पाषाणयुगीन मानव का निवास था। मात्र इ.सा.पूर्व चार हजार वर्ष पूर्व के, शैलचित्र विदर्भ में एक गुफा में पाये गये, जो विदर्भ के अतिप्राचीन इतिहास के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत विश्वसनिय प्रमाण (Evidence) है। इ.सा. पूर्व 1000 वर्ष में (आज से तीन–साडे तीन हजार वर्ष पूर्व) विदर्भ में लोहयुगीन मानव का निवास था, जो विदर्भ का प्रथम किसान एवं कारीगर या आज विदर्भ का पुरातत्वीय प्रमाण के आलेख तीन–साढे तीन हजार वर्ष इतना प्राचीनतम् है।

संपूर्ण भारत में नहीं अपितु भारतीय उपखंड में भी नहीं ऐसी महापाषाण युगीन लोहभट्टी (लोहा तैयार करने वाली भट्टी) नागपूर जिले में पारशिवनी तालुका में नैकुंड नामक वनवासी ग्राम में खुदाई (Excavation of Megalithic Site) में प्राप्त है। जिसके पुरावशेष आज पूर्ण के विख्यात डेक्कन कॉलेज के संग्रहालय में प्रदर्शित है। यह विदर्भ का पुरातत्व है।

प्राचीन काल में इस क्षेत्र में घना अरण्य था जिसका संदर्भ दण्डकारण्य अख्यान में आज भी व्याप्त है। विदर्भ नामक किसी राजा ने आर्य (सुसंस्कृत) सभ्यता की नींव यहां डाली, एवं इस क्षेत्र को हराभरा किया। उसी राजा के (नृपति) स्मृति में यह नाम (विदर्भ) इस क्षेत्र को दिया गया। भागवत पुराण (5.4.10) में विदर्भ नृपति ऋषभदेव का पुत्र इस क्षेत्र का आद्यनृपति था। इस क्षेत्र की प्राचीन राजधानी कुंडीनपूर (अमरावती– वर्धा जिला) थी। जो आज भी कौडिन्यपूर इस नाम से सुप्रसिद्ध है। इसी क्षेत्र से भगवान श्रीकृष्ण ने मांता रूक्मिणी का हरण किया था। जो आगे चलकर भगवान की अग्रमहिषी बनी। एक अर्थ में (महाभारत इ.सा. पूर्व 3132) यह क्षेत्र श्रीकृष्ण की ससुराल थी। नलराजा (निषादराज) एवं दमयंती इसी क्षेत्र को प्रयम वदरातर (वर्धा नदी के किनारे का क्षेत्र) यह नाम था। नलचंपू काव्य में यह श्लोक सुप्रसिद्ध है (6–66 अध्याय 7) –

वीर पुरुष तदेतद्वरदातटनामकं महाराष्ट्रग दक्षिणसरस्वती सा वहाति विदर्भा नदी यंत्र

यह श्लोक आज से 9200 वर्ष प्राचीन संदर्भयुक्त है। विदर्भ के क्षेत्र में अनेक नृपतियों का राज्यशकट चलता था। इ. सा. पूर्व 300–350 से मौर्य, शुंग, कण्व, सातवाहन, श्रत्रप मुंड, वाकाटक, कलचुरी, चालुक्यः राष्ट्रकुट, परमार, यादव, ढाहामनी, गोंड, मराठा, एवं अंग्रेज आदि राजवंश विद्यमान थे। आर्थिक दृष्टि से विदर्भ अत्यंत प्रगत राज्य था। यहां भंडारा जिले में अडम् नामक जगह में टायबेरिस राजा का सुवर्ण सिक्का (Golden Coin) प्राप्त हुआ, जो यूरोपियन राजसत्ता का सिक्का था। जिसका प्रमाण यह स्थायी करता है कि विदर्भ से कई प्रकार का व्यापारिक माल (मसाला, सागवान, कुछ स्पटीक पाषाण, लोहा) देश में जाता था। यह एक व्यापारिक क्षेत्र या इस क्षेत्र में मौर्य पूर्वकालीन आहत सिक्के (पंचमार्कड् क्वाईन्स) भी मिले है जो आर्थिक सुबता का लक्षण है।

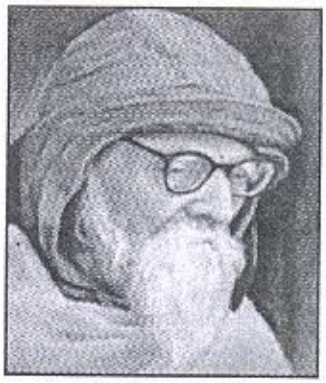

:: विनोबा भावे ::

भूदान आंदोलन के जरिए समाज में भूस्वामियों और भूमिहीनों के बीच की गहरी खाई को पाटने का एक अनूठा प्रयास किया।

भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय सिक्कों का स्थान (Numisunatical India) अनन्य साधारण है। विदर्भ में अनेक नृपतियों के सिक्के मिले है। जो विदर्भ का ऐश्वर्य उजागर करता है। इस क्षेत्र में वाङःमय, स्थापत्य, कला, शिल्प, गुफा, स्थापत्य व्यापार एवं देवालय स्थापत्य का एक वित्रिगिषु आलेख है। महाकवि कालिदास इसी क्षेत्र के रामटेक स्थित राजा के दरबार में ये वाकाटक नृपतियों के राजदरबार के विद्वान सदस्य थे। उत्तर भारत में सुवर्णयुग जो गुप्त

(शेष पृष्ठ 29 पर)

दीनदयाल बहूद्देशीय प्रसारक मंडल, यवतमाल द्वारा संचालित

दीनदयाल किसान विकास प्रकल्प

योजना, कार्यान्वयन तथा उपलब्धियाँ

किसान अल्प मात्रा में क्यों न हों, सिंचित भूमि बना सकें, दुग्ध व्यवसाय हेतु चारा उत्पादन कर सकें और भूजल का स्तर अच्छा बने इसलिये संस्था ने "जलभूमि विकास प्रकल्प" प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत खेत–तालाब, वनराई बाँध, गैबियन बाँध, कोल्हापुरी बाँध आदि के माध्यम से सिंचित क्षेत्र बनाने की संस्था की योजना है।

■ प्रदीप वडनेरकर

प्राकृतिक विपदा तथा सरकारी नीति की दोहरी मार (आसमानी तथा सुल्तानी संकट) से ग्रस्त अन्नदाता (किसान) की आत्महत्याओं की भीषण वास्तविकता को देखते हुए इस समस्या के समाधान के लिये तथा पीड़ित परिवार की सहायता करने हेतु दीनदयाल बहूद्देशीय प्रसारक मण्डल ने सन् 2006 में "दीनदयाल किसान विकास प्रकल्प" प्रारंभ किया।

इस प्रकल्प में मुख्यतः (1) आत्महत्या ग्रस्त किसान परिवार के कल्याण हेतु तथा (2) आत्महत्यायें रोकने के लिये किसानों के समक्ष एक रचनात्मक आदर्श प्रस्तुत करने हेतु कुछ योजनायें, कार्यक्रम, उपक्रम शुरू किये गये। इन्हीं का चार वर्ष का यह संक्षिप्त ब्यौरा है।

(अ) पीड़ित परिवार के कल्याण हेतु कार्यक्रम, उपक्रम

(1) भैयादूज कार्यक्रम : पीड़ित परिवारों को मानसिक तथा आर्थिक सम्बल मिले इस हेतु प्रतिवर्ष संस्था के कार्यकर्ता उस परिवार में जाकर यह कार्यक्रम मनाते हैं। इसमें वस्त्रालंकार, श्री लक्ष्मीजी का चित्र, मिष्ठान्न, दीपक आदि गृहोपयोगी वस्तुयें भेंट की जाती हैं। (सन् 2007 से 2010 तक कुल 189 परिवारों में यह कार्यक्रम मनाया गया) सन् 2010 में परिवारों में न जाते हुये यवतमाल तथा पांढरकवडा इन दो स्थानों पर 100 परिवारों को सम्मानपूर्वक बुलाकर भैयादूज का कार्यक्रम हुआ। वर्ष 2007 में सौरदीप (लालटेन) तथा 2010 में कुकर संच तथा कम्बल हर परिवार को प्रदान किया गया।

(2) परिवार दत्तक योजना (आर्थिक सहायता योजना) : पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता के रूप में व्यवसाय का साधन देने की योजना में 120 परिवारों को संस्था ने दत्तक लिया है।

आज तक 20 परिवारों को बकरीपालन, छह को सिलाई मशीन, एक को सब्जी की दुकान, एक को चप्पल दुकान, एक को आटा चक्की इस तरह से 29 परिवारों के रोजगार की व्यवस्था की है।

(3) छात्र दत्तक योजना : पीड़ित परिवारों में से 5वीं से 10वीं पढ़ने वाले छात्र–छात्राओं की सम्पूर्ण व्यवस्था यवतमाल के विवेकानंद छात्रावास तथा तेजस्विनी छात्रावास में की जाती है। इस तरह 2007 से 2010–11 तक कुल 26 छात्र–छात्राओं की व्यवस्था की गयी।

(4) छात्रवृत्ति योजना : 10वीं के पश्चात् घर रहकर ही शिक्षा प्राप्ति संभव हो इसलिये पीड़ित परिवार के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। वर्ष 2007 में केरल के माता अमृतानन्दमयी ट्रस्ट के सहयोग से 150 छात्रों को प्रति छात्र 400 रुपए छात्रवृत्ति दी गयी। तदनन्तर वर्ष 2010–11 में कुल 8 छात्रों को प्रति छात्र 3,000/– रुपए छात्रवृत्ति दी गयी।

(5) स्वास्थ्य योजना : पीड़ित

:: राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी ::

विदर्भ के आर्वी जिला वर्धा में जन्म स्वदेशी जागरण मंच तथा अन्य अनेक देशव्यापी संगठनों के जनक

परिवारों के स्वास्थ्य की देखभाल की अत्यंत आवश्यकता है। उनमें हिमोग्लोबि की मात्रा चिंताजनक रूप में घट गयी दिखायी देती है। तथैव आर्थिक समस्या के कारण अन्य गंभीर बीमारियों की ओर भी ध्यान नहीं है। इस योजना के अंतर्ग पीड़ित बहनों की सहायता की जाती है स्वास्थ्य संबंधी मार्गदर्शन भी किया जाता है।

मार्च 2010 में आयोजित 'स्नेहमिलन' कार्यक्रम में (भगिनी सम्मेलन) 110 बहनों के स्वास्थ्य की जाँच की गयी। इनमें से को विभिन्न बीमारियाँ थी तथा 10 बहनों को तुरंत शल्यक्रिया सहायता जरूरी थी। इस तरह 41 बहनों का इलाज किया गया, 2 को शल्यक्रिया हेतु सहायता प्रदान की गयी। एक परिवार के बच्चे की आँख का इलाज किया गया।

(6) स्नेहमिलन कार्यक्रम : पीड़ि

परिवारों का हौसला बंधाने के लिये 'समुपदेशन' की आवश्यकता होती है। अतः ऐसे परिवारों की बहनों का सम्मेलन आयोजित कर उसमें मानसिक दृष्टि से मजबूत बनाने हेतु मार्गदर्शन किया जाता है। मार्च 2010 में सम्पन्न कार्यक्रम में 90 बहनों की उपस्थिति रही।

(ब) आत्महत्याओं की रोकथाम हेतु चलने वाले उपक्रम :

पीड़ित परिवारों की सहायता करने के साथ–साथ आत्महत्यायें न हो इसलिये किसानों के समक्ष कुछ रचनात्मक आदर्श रखना जरूरी है। संस्था द्वारा किये गये सर्वेक्षण में आत्महत्या के कारण खोजे गये और तदनुसार योजनायें कार्यान्वित की गयी।

(1) बजट गट : यद्यपि महिला बचतगट संकल्पना प्रचलित है किंतु पुरुष किसानों के बचतगट बनाकर उसके द्वारा परस्पर सहयोग, बचत की आदत, हिसाब रखने की आदत आदि के द्वारा खेती पूरक व्यवसाय चलाने के लिये यह उपक्रम शुरू किया गया। इस हेतु सर्वाधिक आत्महत्याग्रस्त 'केलापूर' तहसील के 40 गांवों का चयन किया गया। उनमें 33 बचतगट शुरू किये गये। उनमें से आज 16 स्थानों पर 24 बचतगट काम कर रहे हैं।

(2) कृषि आधारित उद्योग : संस्था द्वारा किये गये सर्वेक्षण में ध्यान में आया है कि किसान आत्महत्याओं का एक कारण कृषि आधारित उद्योगों का अभाव यह भी है। अतः ऐसे उद्योग किसान शुरू करे यह प्रयास भी संस्था कर रही है। ऐसे उद्योगों के लिये 6 बचतगट बनाये गये हैं। मार्च 2011 तक ये उद्योग प्रारंभ हो जायेंगे ऐसी योजना है।

(3) सेन्द्रिय खेती : आधुनिक तकनीकी के नाम पर चल रही महंगी खेती छोड़कर पारंपरिक सेन्द्रिय खेती किसान करें इस हेतु उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है। खेती की लागत कम हों, उत्पादन लगातार मिले और भूमि की उर्वरता भी बनी रहे इसलिये यह योजना चल रही है। इसमें सेन्द्रिय खेती प्रशिक्षण, सेन्द्रिय खेती के लिये वित्तीय सहायता (Micro Finance), बीज उपलब्ध करा देना ऐसे उपक्रम चलाये जाते हैं।

(4) बचत गटों को लघु वित्त पूर्त्ति (Micro Finance) : सेन्द्रिय खेती तथा खेती आधारित उद्योगों हेतु ब्याज रहित ऋण की पूर्त्ति की जाती है। तदनुसार वर्ष 2008 में एक, वर्ष 2009 में पांच तथा वर्ष 2010 में छह बचत गटों को ऋण वितरित किया गया।

(5) प्रशिक्षण : खेती आधारित उद्योग एवं सेन्द्रिय खेती को परिष्कृत रूप देने हेतु कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। इस तरह अब तक बकरीपालन, दुग्धव्यवसाय, बचतगट आदि के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं।

(6) किसान पर्यटन : किसानों में कृषि तंत्र का अच्छा ज्ञानवर्धन हो, वे सेन्द्रिय खेती करने के लिये उद्यत हो, इस हेतु किसान पर्यटन आयोजित किया जाता है। इसमें कृषि प्रदर्शनी दिखाने तथा सेन्द्रिय खेती दिखाने के कार्यक्रम तय किये जाते हैं। वर्ष 2008 में पुणे की कृषि प्रदर्शनी देखने 14 किसान गये थे, सेन्द्रिय खेती देखने वर्ष 2009 में 30 किसान तथा वर्ष 2010 में 23 किसान सम्मिलित हुए थे।

(7) जलभूमि विकास प्रकल्प : किसान अल्प मात्रा में क्यों न हों, सिंचित भूमि बना सकें, दुग्ध व्यवसाय हेतु चारा उत्पादन कर सकें और भूजल का स्तर अच्छा बने इसलिये संस्था ने "जलभूमि विकास प्रकल्प" प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत खेत–तालाब, वनराई बाँध, गैबियन बाँध, कोल्हापुरी बाँध आदि के माध्यम से सिंचित क्षेत्र बनाने की संस्था की योजना है।

अक्टूबर 2010 में इस प्रकल्प का शुभारंभ होकर एक वनराई बाँध बचतगट की सहायता से बनाया गया। मार्च 2010 तक 20 वनराई बाँध, दो गैबियन बाँध बनाने का संस्था का संकल्प है। ❑

(पृष्ठ 27 का शेष. . .)

प्राचीन विदर्भ . . .

कालखंड की प्रेरणा थी वहीं सुवर्णयुग अपने विदर्भ में इ.सा. की चौथी शताब्दी से इ.सा. की छटवीं शताब्दी में शास्वत थी। जिसे (300 वर्ष) विदर्भ का सुवर्णयुग कहा करते थे। विदर्भ में मनसर, अडम, कौदिण्यपुर, भद्रावती, वत्सगुल्म, आर्णी भोत, देवटेक, मुलचेरा, नंदीवर्धन रामटेक यह सब प्राचीन, नगर एवं ग्राम है। मनसर (जि. नागपूर तालुका रामटेक) के खुदाई में जो वास्तु मिली है उसे हम लोग विदर्भ का नालंदा कहते है। व्यापारी दृष्टि से गत 1500 वर्ष में विदर्भ भारत का दक्षिण भारतीय अर्थ केंद्र था, जहां से संपूर्ण दक्षिण भारत का अर्थ व्यवहार चलता था। आज का जो महाराष्ट्र है वह क्षेत्र की विदर्भ में ही अंतर्भूत था। यहां की वैदर्भी रीति वाडमय की पूर्णावस्था थी। हमारा विदर्भ गत 2000 वर्षों से दक्षिण भारत क्षेत्र में अग्रसर रहा। सभी क्षेत्र का विहंगावलोकन से (आर्थिक, सामाजिक, राजकीय कला एवं व्यापार साधना) यह निश्चित होता है कि अपना आज का विदर्भ प्रांत (11 जिलों) संपूर्ण भारत में दैदिप्यमान एवं प्रसिद्ध क्षेत्र था। ❑

प्रदूषित होती जीवनदायिनी

भारत नदियों का देश है। न जाने कब से प्रकृति ने अपनी गोद में बसने वाले लाखों जीव–जन्तु, पशु–पक्षी और मानव सबका पोषण करने के लिये यह अमृत तुल्य जल प्रवाह बहाया है। मानव ने जब अपनी आँख खोली तो उसे पानी की जरूरत महसूस हुयी। इसके ही किनारे पर उसने अपना डेरा डाला। यहाँ सभ्यतायें विकसित हुयी. . .

■ अमोल पुसदकर

:: डॉ. मधुकर गोविंद बोकरे ::
स्व.जा.मं. के प्रथम राष्ट्रीय संयोजक
नागपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति
हिंदू अर्थशास्त्र के लेखक

क्या आप जानते हैं रोज़ाना 4500 लोग दूषित पानी पीने से मौत को गले लगाते हैं? यह एक भयावह और चौकाने वाला सत्य है जो एक सर्वेक्षण में पाया गया है। भारत नदियों का देश है। चार प्रमुख तथा 55 उपनदी और सैकड़ो छोटे बड़े पानी के स्रोत अपने साथ लाखो लीटर गंदा पानी जो उद्योग, कृषि तथा नगरों से प्राप्त होता है बहाके ले जाने के लिये मज़बूर हैं। और इसका परिणम है स्वच्छ तथा पीने के योग्य पानी की कमी। मनुष्य तथा मवेशियों का जीवन भी जिससे खतरे में पड़ा है ऐसी ये समस्या है।

भारत नदियों का देश है। न जाने कब से प्रकृति ने अपनी गोद में बसने वाले लाखों जीव–जन्तु, पशु–पक्षी और मानव सबका पोषण करने के लिये यह अमृत तुल्य जल प्रवाह बहाया है। मानव ने जब अपनी आँख खोली तो उसे पानी की जरूरत महसूस हुयी। इसके ही किनारे पर उसने अपना डेरा डाला। यहाँ सभ्यतायें विकसित हुयी – इतिहास लिखा गया – वेदऋचाओं का गान हुआ।

इस धारा में घुलमिलकर,
वीरों की राख़ बही है।
इस धारा की कितने ही
ऋषियों ने शरण गही है।
इस धारा की गोदी में
खेल इतिहास हमारा।
यह पुण्यप्रवाह हमारा।

हर नदी के नाम का एक अर्थ है। उसके जन्म कि एक कहानी है। लोगों की भावनायें, श्रद्धायें इससे जुड़ी हैं। कोई गंगाजी को ब्रह्मदेव की कव्या कहता, तो कोई उसे शिवशंकर की जटा से निकलने के कारण शिवसुता कहकर पुकारता है। यमुना को सूर्यकन्या एवं 'यम' कि बहन कहा जाता है – 'यमी' यानि यमुना।' रथसप्तमी के दिन ही नर्मदा भगवान शंकर के सामने प्रकट हुयी थी। गोदावरी दक्षिण गंगा है और वो भारत की दूसरे क्रमांक की बड़ी नदी है जिसे (वर्धा–वैनगंगा प्राणहिता), पेनगंगा मंजिरा आदि नदियाँ मिलती हैं। क्षिप्रा का नाम सम्राट विक्रमादित्य और शरयु का प्रभु राम से नाम जोड़ा जाता है। सिंधु हमारी पहचान है। रावी के तट पर ही संपूर्ण स्वातंत्र्य कि शपथ ली गयी थी। यमुना में जहर फैलने वाले कालिया को कृष्ण भगवान् ने समाप्त किया था।

यमुना कहती कृष्ण कहाँ है,
शरयु कहती राम कहाँ।
व्यथित गंडकी पूछ रही है,
चंद्रगुप्त बलयाम कहाँ।।

आज गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, सिंधु, गोदावरी और महाराष्ट्र में बहने वाली गोदावरी, बैनगंगा, वर्धा, पैनगंगा, कन्हान, धाम, वेणा, कृष्ण, तापी आदि प्रदूषण से ग्रस्त है।

नदी को पानी कहने वाली संपूर्ण मानव जाति है तो गंगा मैया कहने वाला हमारा भारतीय समाज है। जिसने जन्म दिया उसे माता तो प्राणी भी समझता है परंतु जो अचेतन होते हुये भी अस्थि मज्जा के इस देह को चैतन्य प्रदान करती है उसे माँ कहना यह पशुत्व से मनुष्यत्व को पाने का प्रयास है। यह प्रयास करने वाला हमारा समाज है और इसीलिये – **युनान मिस्र रोमा, मिट गये सब जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी**

आने वाले भारत की नदियों को स्वच्छ जल और उसे प्रणाम करने की परंपरा देना यही 'स्वदेशी पर्यावरण रक्षण' की हमारी परंपरा है।

आज अगर 'महर्षि व्यास' यमुना किनारे आते हैं तो उन्हें दृश्य दिखा देगा? यम्नोत्री से निकलने वाली निर्मल यमुना करीब 370 किलोमीटर का प्रवास करके जब दिल्ली के निकट वजीराबाद तक आती है तो पूर्णतः शुद्ध स्वरूप में किंतु दिल्ली छोड़ते समय वो कई उद्योगों रिफायनरीज और जनता द्वारा फैंका गया कूड़ा–कचरा लेकर पूर्णतः अशुद्ध होकर जाती है। करोड़ों लोगों की प्यास बुझा

वाली यमुना कि स्थिति हमें कुछ करने के लिये प्रेरित नहीं करती?

महाराष्ट्र में नागपुर की प्यास बुझाने वाली कन्हान का दृश्य मैंने नागपुर जिले में 'कुही' नामक ग्राम के पास देखा वह तो इतना भीषण था कि जैसे ही मैंने दिनभर यात्रा की, थकान मिटाने के लिये अपने हाथों में पानी लिया तो मैंने अक्षरशः नाले की गंदगी हाथों में पायी!

यह हाल पूरे भारत का है। स्वदेशी जागरण मंच विदर्भ (महाराष्ट्र) ने अपने प्रदेश में इस हेतु विभिन्न स्थानों पर जनता को जागृत, क्रियाशिल एवं संगठित करने के लिये कार्यक्रमों की योजना की है।

गत 12 फरवरी 2011 को वर्धा जिले के पवनार नामक ग्राम में पूज्य विनोबा भावे के आश्रम के समीप 'धाम' नदी के पूजन एवं 'घाट' की स्वच्छता का कार्यक्रम लिया।

प्रदूषण रूपी जहरीले कालिया को मारने में जनता जनार्दन सक्षम है उसे जागृत करने के लिये यह निवेदन आपकी सेवा में प्रस्तुत है। ❑

(लेखक स्व.जा.मं. (विदर्भ) प्रांत के संयोजक हैं।)

(पृष्ठ 26 का शेष. . .)

प्रस्तावित ताप विद्युत केंद्रों से विदर्भ का विकास. . .

प्रदूषण बढ़ाने में सहायक होगी। साथ ही प्रत्येक प्रकल्प की चिमनी द्वारा हवा में छोड़ी जाने वाली राख से 10 से 12 किमी. तक के क्षेत्र के कृषि को खतरा पैदा हो सकता है। राख फसलों के पत्तो पर बैठने से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कमी आती है। परिणामतः उत्पादन में कमी होकर प्राणवायु निर्मिति की मात्रा में भी कमी होगी।

(3) प्रतिदिन लगने वाले 35 टी.एम.सी. पानी की आवश्यकता को देखते हुए भविष्य में अनेक नए, पुराने जल संग्रहों को इस प्रकल्प के लिए आरक्षित किया जायेगा इसका परिणाम सामान्य नागरिक, पशु–पक्षी, प्राणी इन पर पानी की भारी कमी के रूप में होगा। जैव विविधता को बड़ी मात्रा में खतरा उत्पन्न होगा।

(4) प्रकल्प को दिए जाने से पानी की भारी किल्लत होगी। परिणामस्वरूप पानी की दरों में भारी वृद्धि का सामना आम नागरिक एवं किसान को करना होगा। वर्तमान में दो समय की रोटी को तरसता किसान पेयजल का बढ़ा हुआ शुल्क कहां से अदा कर पायेगा?

(5) सिंचित कृषि के साथ सुखे क्षेत्र की कृषि पर भी भारी संकट निर्माण होगा। विदर्भ की कृषि एवं किसान पर यह बड़ा अन्याय और आघात होकर इसके विघातक परिणाम सामने आयेंगे।

यह सब किसलिए? मात्र बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित संबंधों को कायम रखने के लिए। हमारे राष्ट्र के नीति निर्धारकों को यह कौन समझायेगा कि इस देश के प्राकृतिक संसाधनों पर (जंगल, भूमि, कोयला, पानी आदि) सबसे पहला अधिकार इस देश के स्थानीय नागरिकों का है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के फायदे के लिए इस अमूल्य संपत्ति का दोहन कदापि नहीं होने देना चाहिए। विदेशी उपनिवेश के रूप में विकसित होने वाली सेझ और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए विद्युत आपूर्ति करने हेतु हम और कितने किसानों की बलि देंगे?

अतः हम कृषि, किसान एवं पर्यावरण हितों की रक्षा हेतु स्वदेशी जागरण मंच जनता के साथ मिलकर ऐसे ताप बिजली प्रकल्पों का प्रखर विरोध करेगा। ❑

विदर्भ विशेषांकाला हार्दिक शुभेच्छा

नवयुग विद्यालय शिक्षक कर्मचारी

सहकारी पतसंस्था म., नागपूर

कार्यकारी मंडळ

मिलिंद कांबळे
अध्यक्ष

अनिल निघोट
(सचिव)

गोविंद सालपे
(सहसचिव)

श्रीकांत गडकरी
(उपाध्यक्ष)

उमेश जोशी
(कोषाध्यक्ष)

सदस्य

ज्ञा.तु.बसेशंकर, यो.सी.बन, चं.द.गाढवे, ना.ना., लाखे,
सौ. विजया गद्रे, सौ. मोहिनी जोशी, र.ध.वैद्य, सौ. शोभा महाजन

बजट 2011–12 में आम आदमी गायब

बदलते दौर में आम बजट की कोई जरुरत ही नहीं रह गई है। लोकसभा में बस एक रस्म अदायगी मात्र ही है। सरकार सब कुछ खुले बाजार के हवाले कर रही है। जिससे किसी भी चीज की कीमत कमी भी बढाने के लिए सब अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र है। सरकार भी बीच–बीच में कीमतें बढ़ाने में अपना सहयोग देती ही रहती है।

■ डॉ. सूर्यप्रकाश अग्रवाल

केन्द्र की संप्रग सरकार के कांग्रेस दल के वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने 28 फरवरी 2011 को लोकसभा में अपना आम बजट 2011–12 प्रस्तुत कर रस्म अदायगी की क्योंकि वे पैट्रोल व डीजल के दाम व करों की दरों में पहले ही छेडछाड कर चुके थे सो इस बजट में नया कुछ आने का अनुमान नही था सो ऐसा ही हुआ। सत्ता पक्ष के लोगों ने बजट की सराहना की जबकि विपक्ष ने बजट को कोसा और आम आदमी ने स्वंय को बजट में से ही गायब पाया। कुछ लोग इस बजट को एक एकाउंटेंट का बजट बता रहे है तो कुछ लोग इसको टाइम पास बजट बता रहे है।

चार करोड़ लोगों की आठ करोड़ आंखों ने टीवी पर वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी के भाषण में स्वंय को तलाशा परन्तु उसको हताश ही हाथ लगी। स्वयं वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने भी स्पष्ट किया कि केन्द्र सरकार से नाखुश आम जनता को बजट के माध्यम से खुश करने का उनका कोई मकसद नहीं था। सबकी सब रियायतें एक हाथ से दी गई और दूसरे हाथ से वापस ले ली गई। बढ़ती महंगाई से बुरा कोई टैक्स नहीं होता है और वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी चाह कर भी कोई रियायतें नहीं दे सके हैं। इस बजट से केन्द्र सरकार के प्रति आम आदमी की नाराजगी दूर होने वाली नहीं है।

उद्योग जगत ने बजट का स्वागत करते हुए स्टाक एक्सचेंज में सेंसेक्स की छलांग लगवा दी। बजट में आर्थिक सुधारों का अभाव है। सब्जी उत्पादन, दाल

उत्पादन, दूध उत्पादन पर सरकार का ध्यान है व सरकार इनके उत्पादनों को बढ़ाने के लिए पैसा व्यय करेगी। आंगनवाडी के वरकर्स की आमदनी बढ़ेगी व आयकर की छूट की सीमा भी 1.60 लाख रुपये से मात्र 20 हजार रुपये बढा कर 1.80 लाख रुपये ही की गई। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने मंहगाई पर लगाम लगाने के कुछ उपाय किये है परन्तु उनके परिणाम आने में समय लगेगा। यदि मध्य एशिया में हो रही उथल–पुथल के कारण पैट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़े तो वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी के द्वारा इस बजट में महंगाई रोकने के लिए किये गये उपाय भी धरे धराये रह जायेगें। सरकार ने देश की कृषि क्षेत्र को सुधारने के लिए अपर्याप्त उपाय किये गये है। सरकार कृषि क्षेत्र में आमूल चूल बदलाव लाने का साहस नहीं जुटा पाई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कोई नया आयाम नहीं दिया जा सका है। कुछ अन्य क्षेत्रों में बहुत कम सुधार किये गये हैं ।

वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की इच्छा इस वर्ष भारत में अधिक 'पारदर्शी और परिणामोन्मुखी आर्थिक प्रबंधन तंत्र' की ओर एक कदम बढ़ाने की थी और वित्त मंत्री को लगता है कि कर प्रशासन में सुधार और करों और उसकी दरों में आधुनिकता का चोला ओढ़ाना इन प्रयासों की परिणति होगी। गरीब आदमी की

स्वयं वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने भी स्पष्ट किया कि केन्द्र सरकार से नाखुश आम जनता को बजट के माध्यम से खुश करने का उनका कोई मकसद नहीं था। सबकी सब रियायतें एक हाथ से दी गई और दूसरे हाथ से वापस ले ली गई। बढ़ती मंहगाई से बुरा कोई टैक्स नहीं होता है और वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी चाह कर भी कोई रियायतें नहीं दे सके हैं।

सीधे सब्सिडी देने की बात कहीं गई है। कैरोसीन, एलपीजी व खाद पर अब सब्सिडी का पैसा सीधा गरीब उपभोक्ताओं को दे दिया जायेगा। क्या इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकेगी?

अब कैरोसीन, एलपीजी और खाद बिना किसी सब्सिडी के मिलेंगे और गरीबों को नकद पैसा दिया जायेगा ताकि उन्हें गैस, कैरोसीन व खाद महंगा न लगे। परन्तु इससे तो नकली गरीब लोग सामने आकर कहा करेगें कि हमें भी सब्सिडी दो। इससे तो भ्रष्टाचार आम आदमी तक तेजी से पहुंच जायेगा। सरकार तीन रुपये देकर चार रुपये वापस लेना चाहती है।

आमतौर पर यह बात उभर कर सामने आ रही है कि इस बजट में कोई खास बात नहीं है। बजट में जो चीजें महंगी की गई है उन चीजों के उपभोक्ता इस बढती महंगाई का बोझ उठाने में सक्षम है। हवाई यात्रा, ब्रांडेड सोना, रेडीमेड ब्रांडेड कपडे महंगे होगें। यह सब चीजें वे लोग ही क्रय करते है जो इनको क्रय करने में सक्षम है। बिना सिले कपडे, सूटिंग, शर्टिंग सिंथेटिक कपड़े के दाम तो बजट से पहले ही काफी बढ़े हुए है। मारकीन व कॉटन के दाम तो बजट से पहले ही बढ़े हुए थे। सभी प्रकार के कपड़े के दाम बजट के पारित होते ही और बढ़ जायेगें और गरीब व अमीर सभी लोग इस मंहगाई को झेलेंगें।

बड़े लोग होटलों में ठहरते हैं कमरों के किराये बढ जाने से वे ठहरना बंद नहीं कर देगे। जिस कमरे का किराया 1,500 से 50,000 रुपये या उससे अधिक प्रतिदिन है तो इतना व्यय करने वाले लोगों को किराये की वृद्धि महसूस नहीं होगी। और ज्यादातर लोग कम्पनी व सरकार के काम से ही बाहर आते जाते है और होटलों में रुकते है जिनका बिल वे उनसे (कम्पनी अथवा सरकार) वसूल कर लेते है तो इससे कम्पनी के खर्चे व सरकार के खर्चे ही बढ़ जायेंगे जिससे कीमतों पर ही प्रभाव पडेगा।

इसी प्रकार बड़े अस्पताल बडे लोगों के लिए ही हैं महंगे इलाज को वे झेल जायेगें।

साबुन, फ्रिज, एलईडी टीवी, सौर लालटेन, बैटरी वाली कार, मोबाइल सस्ते होने से आम आदमी को लाभ मिल सकेगा। किसानों को कम ब्याज पर ऋण मिलेगा। कम्प्यूटर, प्रिंटर डीवीडी, सीमेंट, व स्टील सस्ते होगें। बेशकीमती पत्थर व पॉम आयल भी सस्ता हेगा। शिक्षा पर व्यय में वृद्धि करके 52 हजार करोड रुपये किये गये है। गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर के नाम पर एक करोड़ रुपये के ईनाम की घोषणा कर कांग्रेस की गुरुदेव के प्रति स्वतंत्रता के 63 साल बाद दी गई सच्ची श्रद्धांजलि ही कही जा सकती है।

इस बजट में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 20 हजार अरब डॉलर कर दी गई । महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की मद में काई वृद्धि नहीं की गई है। देश की आधी आबादी के लिए बजट में कुछ खास रियायत नहीं देखी जा रही है। इस बात में संदेह है कि इस बजट से बढ़ती महंगाई पर लगाम लग सकेगी।

सरकार का मुख्य जोर अर्थव्यवस्था की ऊंची विकास दर (8 से 9 प्रतिशत) को बनाए रखने पर है जिसके लिए आर्थिक सुधार को तेज करना होगा भले ही आम आदमी को महंगाई से ही क्यों ने जूझना पड़े। बजट में युवाओं को रोजगार दिलाने के बारे में भी कुछ भी नहीं कहा गया है। जब तक देश में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन नहीं होता तब तक अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं किया जा सकता है। सरकारी व्ययों पर कोई लगाम नहीं लगाई गई है।

सार्वजनिक कोष का सबसे अधिक व्यय करने वाली कांग्रेस सरकार स्वयं अपने व्ययों पर कटौती करने की कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखा सकी है। इससे लगता है कि राजकोषीय घाटा और बढ़ेगा जबकि वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने का आश्वासन दिया है पर इसके लिए कोई कार्ययोजना प्रस्तुत नहीं करके वे घाटे को बढ़ाने से नहीं रोक सकेगें।

केन्द्र सरकार घपले व घोटालों से घिर गई है। परन्तु वित्त मंत्री ने सरकारी योजनाओं को समय से पूरा करने की भी कोई आदेश व निर्देश नहीं दिये है। आम बजट से केन्द्र सरकार पांच राज्यों में होने वाले विधान सभा चुनावों में अपने हित साधती लग रही है। जिससे आर्थिक सुधार आगे बढ़ते नज़र नहीं आ रहे हैं।

बदलते दौर में आम बजट की कोई जरुरत ही नहीं रह गई है। लोकसभा में बस एक रस्म अदायगी मात्र ही है। सरकार सब कुछ खुले बाजार के हवाले कर रही है। जिससे किसी भी चीज की कीमत कभी भी बढाने के लिए सब अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र है। सरकार भी बीच–बीच में कीमतें बढ़ाने में अपना सहयोग देती ही रहती है। डंकल समझौते में अपना सब कुछ गंवा चुकी सरकार को सारी जनता की सहूलियतें धीरे धीरे समाप्त तो करनी ही है। डंकल समझौते के अतंर्गत तो सारी सब्सिडी व सामाजिक कल्याण के काम सरकार को समय के साथ साथ बंद करने ही है।

आगामी कुछ ही वर्षों में आम जनता को अपने दम पर ही सब कुछ करना पड़ेगा। इस बजट में 130 वस्तुओं को टैक्स के दायरे में लेकर आम आदमी को तो महंगाई क लिए तैयार रहना चाहिए।

शिक्षा पर जीडीपी के 5 प्रतिशत के बराबर व्यय स्तर पर भारत, ब्राजील व चीन एक स्तर पर हो गये है। जबकि रुस 8 प्रतिशत व्यय करता है। विश्व में किसी भी औद्योगिक देश में साक्षरता की दर 80 प्रतिशत से कम नहीं है। इस बजट में इस असंतुलन को दूर करने के लिए कुछ संसाधन तो उपलब्ध कराये ही गये है क्योंकि भारत मे साक्षरता की दर 70 प्रतिशत ही है। ❑

प्रतिक्रिया

ढीला बजट – लेकिन सही दिशा में

बजट के कुछ नकारात्मक बिन्दु भी हैं। ये कांग्रेस की मूल आइडियोलाजी में निहित हैं। कांग्रेस का गेम प्लान है कि बड़ी कम्पनियों को छूट देकर गरीब को त्रास दो और पर्यावरण को नश्ट कर दो। इस कृत्य में अमरीका जैसे देशों का आशिर्वाद लो। फिर इससे जनित जन आक्रोश तथा पर्यावरण की क्षति को रोकने के लिये छोटी–छोटी तमाम योजनायें बनाओ और मूल क्षति से जनता का ध्यान हटा दो। जनता को इस दिखावटी राहत देने के नाम पर भारी नौकरशाही स्थापित करो।

■ डॉ. भरत झुनझुनवाला

वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत बजट कुल मिलाकर सही दिशा में है। बजट के नकारात्मक बिन्दु कांग्रेस की मूल आयडियोलाजी में निहित हैं जोकि वित्त मंत्री की परिधि के बाहर है।

वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स में छूट दी है। सामान्य करदाता के लिये आयकर में छूट 1,60,000 से बढ़ाकर 1,80,000 कर दी गई है। कंपनियों द्वारा देय कार्पोरेट टैक्स पर देय सरचार्ज घटाया गया है। इनकम टैक्स की इस छूट से जनता के हाथ में आय अधिक बचेगी। इससे निवेश बढ़ेगा।

एक्साइज एवं कस्टम ड्यूटी में वृद्धि के साथ–साथ वित्त मंत्री ने चुनिंदा उत्पादों पर छूट बढ़ाई है। हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई गयी है। हाईब्रिड कारों में लगने वाले उपकरणों का आयात सरल किया है। उर्जा की बचत करने वाले सीएफएल लैम्प पर ड्यूटी घटाई गयी है। ये कदम दर्शाते हैं कि वित्त मंत्री पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूक हैं। लेकिन कांग्रेस सरकार ने बड़ी कम्पनियों को पर्यावरण को नष्ट करने की पूरी छूट दे रखी है। थर्मल बिजली संयंत्रों द्वारा जंगल तथा हाइड्रोपावर द्वारा नदियों को नष्ट किया जा रहा है। खनिजों के निर्यात के लिये भी जंगल काटे जा रहे हैं। ये कम्पनियां पर्यावरण की भारी हानि कर रही हैं। दूसरी तरफ वित्त मंत्री सीएफएल लैम्पों के लिये रियायत दे रहे हैं। यह उसी तरह हुआ जैसे किसान की भूमि का अधिग्रहण करने के बाद उसे मनरेगा में 100 दिन का रोजगार देना। जिन उद्योगों के द्वारा पर्यावरण की क्षति की जा रही है उन पर टैक्स बढ़ाना चाहिये था। परन्तु कांग्रेस की आइडियोलाजी बड़ी कम्पनियों पर कुर्बान है। अतः यह कार्य दुष्कर है।

पिछले बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि फर्टिलाइजर सब्सिडी को सीधे किसानों को नगद देने के कदम उठाये जायेंगे। इस बजट में कैरोसीन तेल पर दी जाने वाली सब्सीडी को सीधे बीपीएल कार्ड धारकों को देने की बात कही गई है। मंतव्य सही दिशा में है। जनता के कल्याण के लिये खर्च की जा रही अधिकतर रकम वर्तमान में सरकारी कर्मियों का पेट भरने में खर्च हो रही है। जनता का कल्याण होने के स्थान पर कल्याणकारी माफिया का कल्याण हो रहा है। इस दिशा में घोषणाओं से आगे आने की जरूरत है। सभी सब्सिडी जैसे फर्टीलाइजर, खाद्यान्न, कैरोसीन, शिक्षा, स्वास्थ, आंगनबाड़ी, मिडडे मील इत्यादि को समाप्त करके लाभार्थी को नगद रकम देनी चाहिये।

मेरी गणना के अनुसार इन कार्यक्रमों को समाप्त करके रकम को सीधे जनता को दिया जाये तो प्रति परिवार प्रति माह 2000 रुपये दिये जा सकते हैं। यह रकम बीपीएल तथा एपीएल सभी परिवारों को दिये जा सकती है। सभी को रकम देने से गरीब बने रहने का आकर्षण समाप्त हो जायेगा। इस दिशा में सरकारी नौकरशाही ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं है। वे अपनी कब्र स्वयं नहीं खोदना चाहते। अतः वित्त मंत्री को सख्ती से इस घोषणा को कार्यान्वित करना चाहिये। अन्यथा पिछले साल फर्टिलाइजर सब्सिडी की तरह यह घोषणा भी घोषणा मात्र ही रह जायेगी।

बजट के कुछ नकारात्मक बिन्दु भी हैं। ये कांग्रेस की मूल आइडियोलाजी में निहित हैं। कांग्रेस का गेम प्लान है कि बड़ी कम्पनियों को छूट देकर गरीब को त्रास दो और पर्यावरण को नष्ट कर दो। इस कृत्य में अमरीका जैसे देशों का आशीर्वाद लो। फिर इससे जनित जन आक्रोश तथा पर्यावरण की क्षति को रोकने के लिये छोटी–छोटी तमाम योजनायें बनाओ और मूल क्षति से जनता का ध्यान हटा दो। जनता को इस दिखावटी राहत देने के नाम पर भारी नौकरशाही स्थापित करो। इस नौकरशाही के सहयोग से जन आन्दोलन को कुचल दो। इस आइडियोलाजी के अंतर्गत वित्तमंत्री ने जन कल्याण करने का दिखावा करने वाली तमाम योजनाओं की घोषणा की है। आंगनबाड़ी कर्मियों के वेतन बढ़ाये गये हैं। वृद्धा पेंशन बढ़ाई गयी है। सर्व शिक्षा अभियान, अनुसूचित जातियों के लिये स्कालरशिप शिक्षा तथा स्वास्थ सेवाओं आदि पर खर्च बढ़ाये गये हैं। इन योजनाओं के माध्यम से सरकारी कर्मियों को पोसा जा रहा है।

मेरा मत है कि इन कार्यक्रमों का सही मूल्यांकन किया जाये तो सिद्ध होगा कि ये निष्प्रभावी हैं। इन सभी कार्यक्रमों को बन्द करके जनता को सीधे नगद देने पर विचार करना चाहिये।

वित्त मंत्री ने माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों, छोटे उद्योगों एवं किसानों को सस्ते ऋण उपलब्ध कराने के कदम उठाये हैं। इन्हें दिये जाने वाले ऋण की मात्रा में वृद्धि एवं ब्याज दर में कटौती की गयी है। प्रथम दृष्ट्या यह कदम जनहितकारी दिखता है। इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। मेरा आकलन है कि सस्ते ऋण का लाभ इन लाभार्थियों को नहीं अपितु शहरी उपभोक्ताओं को होता है। सस्ते ऋण से माल की उत्पादन लागत घटती है जो स्वागत योग्य है। परन्तु माल के दाम भी साथ–साथ घट जाते हैं। अंततः लाभार्थी के सर पर ऋण खड़ा रह जाता है जबकि उपभोक्ता को सस्ता माल मिलता है। वित्त मंत्री को चाहिये कि जन हित की कसौटी पर इस आइडियोलाजी का पुर्नमूल्यांकन कराये। इन बिन्दुओं को छोड़कर बजट सही दिशा में है यद्यपि इसकी चाल धीमी है। ❑

वर्तमान बजट वैसे लोगों के लिए है जो पहले से पूंजीपति हैं : मुरलीधर राव

सरकार की उदासीनता के कारण भारतीय बाजारों में विदेशी उत्पाद का वर्चस्व स्थापित हो चुका है उन्होंने केन्द्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि आर्थिक व्यापार के क्षेत्र में विदेशों के साथ सरकार बराबरी से एकरारनामा करे। भारतीय युवक विदेशों में जाकर व्यापार कर सकें यह व्यवस्था होनी चाहिए। – अरुण ओझा

गोड्डा (झारखण्ड) – देश का बजट पेश किया गया, मगर बजट वैसे लोगों के लिए है जो पहले से पूंजीपति हैं। ऐसे पांच प्रतिशत के लिए सरकार सोंचती है जबकि 95 प्रतिशत लोग सर्वाधिक संख्या में है साथ ही हासिये पर हैं। उक्त बातें राष्ट्रीय चिंतक सह स्वदेशी जागरण मंच के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक पी. मुरलीधर राव ने गोड्डा प्रखण्ड के कौआढाव नामक स्थान पर स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आहुत वनवासी किसान महासम्मेलन में महती भीड़ को संबोधित करते हुए कहा। श्री राव ने अपने संबोधन में कहा कि संताल परगना में वीर सिद्धु कान्हु, बैजल बाबा जैसे महानायकों ने जंगल, जमीन और आजादी के लिए जान दी है। सुन्दरपहाड़ी और गोड्डा के आदिवासियों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी। मगर आज उनकी आजादी का फायदा बाहरी लोग ले रहे हैं। श्री राव ने कहा कि आजादी वैसे लोगों के लिए है जो मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों के पूंजीपति हैं।

आगे उन्होंने कहा कि यहां के गरीब आदिवासी किसानों को कृषि ऋण तक नहीं मिल रहा हैं मगर पैसे वालों को कार ऋण आसानी से मिल रहा है। दिल्ली में बैठने वाले नहीं चाहते कि यहां के गरीब किसानों के घर बिजली जले। मगर दिल्ली में इतनी बिजली जलती है कि रात में भी आप चींटी के पाव गिन सकते हैं। सरकार महानगरों में इमारतों के लिए करोड़ों की राशि खर्च कर रही है मगर आदिवासी किसानों के लिए कृषि कार्य के लिए एक बैरवो नाला तक निर्माण नहीं करा पा रही है। जल संचय के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। जबकी सरकार घोटाले पर घोटाले करते जा रही है।

गोड्डा सुन्दरपहाडी, पथरगामा और बोआरीजोर के केन्द्र स्थल कौआढाव स्थित प्रोजेक्ट उच्च विधालय के विशाल मैदान में स्वदेशी जागरण मंच किसान पंचायत के तत्वाधान में आयोजित वनवासी किसान महासम्मेलन कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन राष्ट्रीय चिंतक पी. मुरलीधर राव अखिल भारतीय संयोजक अरुण ओझा क्षेत्रीय सह संयोजक दिनेश मंडल, प्रांत संयोजक सचिन बरियार तथा कार्यक्रम अध्यक्ष लाडली मोहन झा ने संयुक्त रुप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इसके पूर्व नेताओं ने भारत माता सिद्धु कान्हु महात्मा गांधी और राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के तस्वीर पर माल्यार्पण किया। वहीं कार्यक्रम से पूर्व नेताओं ने बैजल बाबा की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।

> **आर्थिक आजादी की लड़ाई के लिए वनवासी तैयार रहे हैं। क्योंकि यह देश आर्थिक रुप से गुलाम हो चुका है।**
> – अरुण ओझा

स्वदेशी जागरण मंच द्वारा गोड्डा प्रखण्ड के कौआढाव में आयोजित वनवासी किसान महासम्मेलन को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रीय संयोजक अरुण जी ओझा ने कहा कि आर्थिक आजादी की लड़ाई के लिए वनवासी तैयार रहे हैं। क्योंकि यह देश आर्थिक रुप से गुलाम हो चुका है। उन्होंने आह्वान किया कि आदिवासी को तिलकामांझी सिद्धु कान्हु बैजल मुर्मू बिरसा मुंडा एवं भागीरथ बाबा बनकर संघर्ष छेड़ना होगा जिससे किसान मजदूरों के घरों में खुशहाली आ सके। श्री ओझा ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि

सरकार की उदासीनता के कारण भारतीय बाजारों में विदेशी उत्पाद का वर्चस्व स्थापित हो चुका है उन्होंने केन्द्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि आर्थिक व्यापार के क्षेत्र में विदेशों के साथ सरकार बराबरी से एकरारनामा करे। भारतीय युवक विदेशों में जाकर व्यापार कर सकें यह व्यवस्था होनी चाहिए। सम्मेलन में लगभग पन्द्रह हजार आदिवासी स्त्री पुरुष परम्परागत वेष भूषा म आय थ। नृत्य और वाद्य यंत्रों के साथ आदिवासियों ने स्वदेशी नेताओं का स्वागत किया।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए क्षेत्रीय सह संयोजक दिनेश मंडल ने कहा यहां के किसानों की दुर्गति सरकार की गलत नीतियों के कारण जबकि प्रांत सचिन्द्र बरियार ने उदारीकरण पर रोक लगाने की मांग की। कार्यक्रम को प्रांत सह संयोजक राजेश उपाध्याय कार्यक्रम संयोजक ज्ञान टुडू अनिल मुर्मू जीसु राम मरंडी सहित अनेक नेताओं ने सम्बोधित किया। कार्यक्रम में मुख्य रुप से प्रन्त विचार मंडल इंन्द्रजीत तिवारी विभाग संयोजक विष्णु सिंह राष्ट्रीय परिषद सदस्य उषा जायसवाल प्रान्त सह संघर्ष वाहिनी प्रमुख जय प्रकाश ओझा प्रांत समिति सदस्य अजय कुमार जिला सहसंयोजक मोसम ठाकुर सहित दजर्णो स्वदेशी कार्यकर्ता उपस्थित थे। ❑

दसवां स्वदेशी मेला (बोकारो) संपन्न

स्वदेशी जागरण मंच महंगाई की इस संभावना को देखते हुए मॉल संस्कृति का विरोध करती है। मूल्य के इस उतार–चढ़ाव के खेल में चार करोड़ खुदरा व्यापारी समाप्त होने जा रहे हैं और उसके साथ 12 करोड़ परिवार भी भुखमरी के कगार पर है।

स्वदेशी जागरण मंच द्वारा 2 फरवरी से 8 फरवरी 2011 तक दसवां स्वदेशी मेला का आयोजन किया गया। 2 फरवरी को उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि अपने स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय विचार मंडल प्रमुख अश्विनी महाजन जी थे।

समापन समारोह के मुख्य अतिथि सांसद पशुपति नाथ सिंह थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा स्वदेशी भारत की जीवन पद्धति का एक माध्यम है और स्वदेशी मेला विकास का मूर्त रूप है। भारत के अर्थनीति की आलोचना करते हुए श्री सिंह ने कहा वित्तमंत्री कहते हैं भारत के लोग का प्रति व्यक्ति आय 5422 रुपए है। गत वर्ष यह आय 4500 रुपए थी। वित्तमंत्री जब प्रतिव्यक्ति आय की बात करते हैं तो टाटा, बिड़ला, अंबानी तथा सारे धनकुबेरों का आय एवं भुखमरी झेल रहे देशवासी की आय को जोड़कर औसत निकाल देते हैं। वित्तमंत्री के हिसाब से भारत समृद्ध है पर सरकार द्वारा गठित आयोग के अध्यक्ष अर्जुन सेन गुप्ता कहते हैं यहां 76 प्रतिशत लोग 20 रुपए प्रतिदिन केवल प्राप्त कर पा रहे हैं। गरीबों के लिए कोई संवेदना नहीं है।

मेले में मुख्य वक्ता के रूप में विचार रखते हुए बिहार–झारखण्ड के क्षेत्रीय सहसंयोजक दिनेश मंडल ने कहा – बोकारो का स्वदेशी मेला स्वदेशी का भरपूर प्रचार–प्रसार करते हुए ग्रामीण एवं कुटीर–उद्योग के उत्पाद को विशेष रूप से प्रदर्शित करता है। यही स्वदेशी मेला का उद्देश्य है। सरकार के तीखी आलोचना करते हुए श्री मंडल ने कहा कुछ दिन पहले प्याज का मूल्य प्रतिकिलो 18 था। अचानक दाम बढ़कर 60 रुपए किलो हो गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे हाथ में जादू की छड़ी नहीं है। मैं क्या करूँ? फिर उन्हें ध्यान में आया बंगाल में चुनाव होने वाला है। भ्रष्टाचार सरकार के गले की हड्डी बनी हुई है। फिर प्याज का मूल्य 20 रुपए किलो पर आ गया।

आखिर ये हो क्या रहा है? वालमार्ट, रिलायंस फ्रेस, डी मार्ट, विशाल मेगामार्ट ये सब आजकल खुदरा व्यापार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अरबों रुपए का प्याज खरीद कर होल्ड कर लिया, मूल्य 60 रुपए चला गया। अपनी नैया सरकार डूबता हुआ देखी तो सभी मॉल पर दबाव डाला मूल्य 20 रुपए पर आ गया। यह विदेशी कंपनियों का प्याज के क्षेत्र में अनियंत्रित एकाधिकार के कारण हुआ।

स्वदेशी जागरण मंच महंगाई की इस संभावना को देखते हुए मॉल संस्कृति का विरोध करती है। मूल्य के इस उतार–चढ़ाव के खेल में चार करोड़ खुदरा व्यापारी समाप्त होने जा रहे हैं और उसके साथ 12 करोड़ परिवार भी भुखमरी के कगार पर है।

विशिष्ट अतिथि बोकारो जिला के आरक्षी अधीक्षक साकेत कुमार सिंह ने स्वदेशी मेला की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा स्वदेशी तथा स्वावलंबन से ही देश का विकास हो सकता है। मेला केवल 7 दिनों के लिए नहीं अपितु लंबे समय के लिए होना चाहिए।

सभा की अध्यक्षता कर रहे संघ के प्रांत संघचालक जगन्नाथ शाही ने कहा बिहार के नेता ने भ्रष्टाचार में क्रीतिमान स्थापित किया था। तमिलनाडु के नेता ने पहले के सभी रिकार्ड तोड़ दिये। ह्वेनसांग जब भारत आया था तो एक दिन एक सराय में ठहरा था। जाते समय उसके असरफी का बटुआ सराय में छूट गया। कुछ दूर निकल जाने के बाद उसे बटुआ की याद आई। बहुत परेशान हो गया। वहाँ एक व्यक्ति गाय चरा रहा था। उसकी परेशानी देखकर उसने पूछा पथिक तुम्हारे परेशानी का कारण क्या है? उसने बटुआ छूटने की बात कहीं तो चरवाहा ने कहा – इसमें परेशान होने की क्या बात है, तुम जाकर देखो, तुम्हारा बटुआ वहीं पड़ा होगा। और वह बटुआ यथावत उसे वहीं पड़ा मिला। भारत का जीवन मूल्य यहां से प्रारंभ होता है। तब यह देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज असमानता और निर्धनता का कारण भ्रष्टाचार है।

स्वागत भाषण प्रांत संयोजक सचिन्द्र कुमार वरियान ने किया। मंच संचालन मेला संयोजक दिलीप कुमार वर्मा ने किया। धन्यवाद ज्ञापन प्रांत के मेला अमरेन्द्र कुमार सिंह ने किया। अजय कुमार चौधरी तथा ज्योतिन्द्र कुमार देव ने किया।

मेला के प्रवेश द्वार पर महर्षि अरविन्द, डॉ. अंबेडकर, दत्तोपंत ठेंगडी जी के चित्र लगे थे। मेला के बीचों–बीच भारत माता का विशाल चित्र लगा हुआ था। इसके आला एक सौ दुकानें मेला में लगी। मेले को देखने के लिए लगभग चार लाख आए। ❑